

cmky

लुटती। अंदरी काया क्षेत्र की कारवाँ-
 धारी ग्रामीण सड़क पर श्रुवावक को
 हुए भीषण सड़क हादसे में साइकिल
 सवार सहित तीन लोगों की मौत हो
 गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से
 घायल हो गया। मुक्तों की पहलान
 मानकीडीह गांव निवासी पूरन मुत्ता
 (47), अमृत पातर (25) और आयुष
 पातर (17) के रूप में हुई है। वहीं
 घायल सुनील पातर (25) का प्राथमिक
 उपचार तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
 में करने के बाद रेफर इलाज के लिए
 रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।
 उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
 स्थानीय लोगों के अनुसार, पूरन मुत्ता
 डोरेया सामाजिक हट से खरीदारी के
 सड़क से अपने घर लौट रहे थे।
 इसी दौरान जेनाडीह के पास पीछे से
 तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार
 टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण
 थी कि पूरन मुत्ता की घटनास्थल ही नहीं
 मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक
 अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई
 और पातर और अमृत पातर, आयुष
 पातर और सुनील पातर गंभीर रूप से
 घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की
 मदद से सभी घायलों को इलाज के
 लिए तमाड़ अस्पताल ले जाया गया।
 तत्पश्चात रास्ते में ही अमृत पातर और
 आयुष पातर ने दम तोड़ दिया।

संक्षिप्त

रांची जिला योग

चैंपियनशिप आज से, तैयारियां पूरी

रांची। दो दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप रांची जिला योग संघ के तत्वावधान में आगामी 11 एवं 12 जुलाई को जीडी गोवंका स्कूल नामकोम रांची में आयोजित की जा रही है। रांची जिला योग संघ की आयोजन सचिव राहुल पोद्दार ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता में रांची जिला के लगभग 500 से ऊपर प्रतिभागी 11 आयु वर्गों में बालक बालिका भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ 11 जुलाई को 12:00 बजे किया जाएगा। दूसरे दिन 12 जुलाई को प्रतियोगिता पूर्वाह्न 8:00 बजे से शुरू होगी। प्रतियोगिता के पहले दिन सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित होगी तथा दूसरे दिन सब जूनियर व जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी वहीं प्रतियोगिता के दूसरे दिन 12 जुलाई को अपराह्न 3:00 से योग टाइटल स्पर्धा शुरू होगी इसके उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित की जाएगी। इसी प्रतियोगिता के आधार पर रांची जिला योग टीम का गठन किया जाएगा। जो चयनित खिलाड़ी आगामी चार्चबासा में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची का प्रतिनिधित्व करेगी।

डिजिटाइजेशन जिन

इलाकों में धीमा है, यहां

कैंप लगाकर तेजी लाएं

: के. रवि कुमार

रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत बुध लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्त्युमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी पात्र मतदाता फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरकर हस्ताक्षर करें और यथाशीघ्र बीएलओ को वापस सौंप दें, ताकि पूर्वाक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईईआरओ), उप निर्वाचन पदाधिकारियों, कंन्चूरट ऑफरैटरों तथा बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में इन्त्युमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य अपेक्षाकृत धीमा है, वहां विशेष शिविर आयोजित कर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि निर्धारित समय के भीतर सभी फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए जा सके। के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि इन्त्युमरेशन फॉर्म के डिजिट पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा ही भरा जाना है। इनपर व्यक्तियों या विदेशी नागरिकों को यह फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत किसी विदेशी नागरिक द्वारा अवैध रूप से फॉर्म भरना, गलत या भ्रामक जानकारी देना अथवा बिना हस्ताक्षर के फॉर्म जमा करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

समारोह

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। रिनपास रांची में प्रोजेक्ट मानस की सफलता पर रोटरी क्लब रांची ने क्लब परिसर में आभार समारोह का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीसीएल के महाप्रबंधक (सीएसआर) सिद्धार्थ शंकर, विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक (वित्त) संजय सिंह एवं रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में रोटरी क्लब और सीसीएल के संयुक्त मुहिम रश्मिवास एवं सेवा का संगम झा सीसीएल एवं रोटरीर के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। चकाओं ने समाज सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की साझेदारी और योगदान को जनहित के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मुख्य अतिथि सीसीएल महाप्रबंधक

रांची विश्वविद्यालय का 67वां त्रिदिवसीय स्थापना दिवस समारोह प्रारम्भ, कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा

हमें रांची विवि की गौरवशाली परंपरा को आगे ले जाना है

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। रांची विश्वविद्यालय का 67वें त्रिवि्दसीय स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ 10 जुलाई को आर्यभट्ट सभागार में हुआ। माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय प्रो. सरोज शर्मा तथा सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा द्वीप प्रज्जवलन और पीएफए विभाग के छात्रों के राष्ट्रगीत और कुलगीत की प्रस्तुति से कार्यक्रम 'प्रारम्भ' शुरू हुआ। सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ एवं स्मृतिचिन्ह और शौल ओढ़ा कर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय प्रो. सरोज शर्मा ने झारखंड की भूमि को नमन करते हुये सबों को 67वें स्थापना दिवस शुभकामनायें दीं और कहा कि 1960 में झारखंड क्षेत्र में स्थापित रांची विश्वविद्यालय की यात्रा बहुत ही गौरवशाली रही है और इसकी परंपरा शिक्षण के क्षेत्र में योगदान अप्रतिम रहा है। यहां विद्वान शिक्षकों की एक परंपरा रही है जिन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं को संदेव निखारने का कार्य किया है। रांची विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों की इतनी समृद्ध सूची है कि हम क्यों नहीं भव्यता से अपना स्थापना दिवस मनायें। हमने एनएसएस, खेल और अकादमिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा किया है। हमने



भारतीय ज्ञान परंपरा को आर्यू में लागू किया है। यह गर्व की बात है कि एनइपी 2020 के अनुसार रांची विवि का पहले बैच के हमारे विद्यार्थी जल्द ही उत्तीर्ण होकर कर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अब पूरी उम्मीद है कि नवगठित विवि आयोग आर्यू की हर प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये त्रिविदसीय समारोह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। अब हमारा ये दायित्व है कि इस गौरवशाली परंपरा को आगे ले जायें। रांची युनिवर्सिटी में आज 1600000 विद्यार्थी यहां एनरोल हैं। यहां हमें इक्वेलिटी के साथ क्वालिटी एजुकेशन देना है। कार्यक्रम में पीएफए विभाग के विवुल नायक की टीम द्वारा रांची

विश्वविद्यालय के 1960से 2025 तक की यात्रा को कोरियोग्राफी 'मैं हूं रांची विश्वविद्यालय' के माध्यम से भव्य प्रस्तुति दी गयी। जिसे देखकर सभागार के सभी दर्शक अभिभूत हो गये और सभागार तालियों से गुंज उठा। टीआर एल के नामपुरी विभाग के छात्र छात्राओं ने करसा नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी।

आर्यू के कुछ विभागों की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही है: नरेन्द्र भगत

1960 से ही आर्यू से जुड़े विशिष्ट अतिथि नरेन्द्र भगत (सेवानिवृत्त आइएस तथा रांची विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार) ने स्थापना दिवस

पर अपनी यादों को साझा किया। उन्होंने सबों को शुभकामनायें देते हुते कहा कि यह 67वां स्थापना दिवस मुझे अतीत की यादों में ले जाता है। मैं विवि की यात्रा का साक्षी भी रहा और सहयात्री भी। रांची विवि ने कइ ईंस्टिट्यूशन को पुष्पित परल्वित किया, जिसमें रिस्स बीएयू जैसे संस्थान थे। 1960 में मैंने यहां पढ़ाई की और 1966 में मैंने पीजी बॉटनी में अध्यापन किया। तब आर्यू के विभागों और प्राध्यापकों की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। तब शिक्षक बहुत ही सादगी से रहते थे। एथ्रोपोलोजी, साइकोलोजी की भी बहुत ख्याति थी। तब कभी भी सेशन या परीक्षा देरी नहीं होते थे। कल्चरल और स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहुत होते थे। मैंने रांची विवि से अपने लगाव के कारण छपरा की कलेक्ट्री छोड़ आर्यू में रजिस्ट्रार का पद ग्रहण किया। इस आयोजन में पूर्व कुलपति प्रो.ए.ए खान, प्रो. कामिनी कुमार, प्रो.अजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।

रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहु ने रांची विश्वविद्याल की विशिष्टता और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय पठन पाठन के अलावा खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अग्रणी है। अभी हमने इस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट

का आयोजन किया था जिसमें हम विजेता रहे। इस अवसर पर फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को मंच पर कुलपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आर्यू के तीन छात्रों दिवाकर आनंद, फलक फातिमा और दीक्षा कुमारी को भी मंच पर कुलपति ने सम्मानित किया। पहले दिन के कार्यक्रम 'आरम्भ' का संचालन सीबीएस की डिप्टि डायरेक्टर डॉ. स्मृति सिंह और डॉ. किशोर सुरीन ने किया तथा धन्यवाद जापन रजिस्ट्रार रांची विवि डॉ. राजकुमार शर्मा ने किया उन्होंने सबों का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम सभी रांची विश्वविद्यालय की पुरानी गौरवशाली परंपरा को बनाये रखने को कृतसंकल्प हैं। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू सीसीडीसी, परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, सभी संकायाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के हेड प्राध्यापक व अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दूसरे दिन 11 जुलाई को कला दिवस के रूप में मनाया जायेगा वहीं 12 जुलाई को हरित विश्वीका का आयोजन होगा। यह दोनों आयोजन शहीद चौक स्थित मुख्ेय प्रशासनिक भवन में होंगे। जिसमें परिसर की दीवारों पर सोहराई पेंटिंग से लेकर पौधापणप के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

रांची विश्वविद्यालय के 67वां त्रिदिवसीय स्थापना दिवस समारोह प्रारम्भ, कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा

हाई कोर्ट ने विलंब से नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को समान वरिष्ठता और सेवा लाभ देने का दिया आदेश

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने उच्च विद्यालयों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या-21/2016) में प्रशासनिक कारणों से विलंब से नियुक्त हुए शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि सहित अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्णय लेकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की

एकलपीठ ने अजय कुमार सहित आठ याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे उसी टीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया के सफल अभ्यर्थी हैं, जिसके तहत अन्य चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति वर्ष 2019 में हो गई थी, जबकि प्रशासनिक कारणों से उन्हें वर्ष 2021 में नियुक्ति मिली। उनका तर्क था कि नियुक्ति में देरी उनकी किसी गलती या लापरवाही के कारण नहीं हुई, इसलिए उन्हें अपने समकक्ष शिक्षकों से कनिष्ठ नहीं माना जाना

चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुमित गडोदिया और अमृतांशु वत्स ने अदालत को बताया कि नियुक्ति पत्र जारी करने में लगभग तीन वर्ष का विलंब हुआ। इस अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। इसके बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए और अंततः याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वर्ष 2021 में उनकी नियुक्ति हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर

से यह भी दलील दी गई कि प्रशासनिक विलंब का प्रतिकूल प्रभाव उन पर नहीं डाला जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो वे बिना किसी पक्ष के अपने ही बैच के शिक्षकों से कनिष्ठ हो जाएंगे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए उच्च वरिष्ठता का लाभ देने की मांग की गई। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाएं

स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 12 सप्ताह के भीतर वर्ष 2019 में नियुक्त समकक्ष शिक्षकों के अनुरूप याचिकाकर्ताओं को समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य संबंधित सेवा लाभ देने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। मामले के सभी याचिकाकर्ता झारखंड के गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित हैं। इनमें पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, चतरा, हनुमान गाँव विरडिह सहित अन्य जिले शामिल हैं।

बीएयू में खरीफ अनुसंधान परिषद की दो-दिवसीय बैठक का समापन

युवा वैज्ञानिक नवोन्मेषी शोध पर ध्यान केंद्रित करें : डॉ एससी दुबे

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ अनुसंधान परिषद की दो दिवसीय बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान प्रयास बढ़ने पर जोर दिया गया। साथ ही अंतर विभागीय एवं अंतर सांस्थानिक सहयोगात्मक शोध प्रस्ताव विकसित एवं कार्यान्वित करने की वकालत की गई। कहा गया कि इससे विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध विशेषज्ञताओं और द्वांचागत सुविधाओं का राज्य हित एवं किसान हित में ज्यादा लाभकारी इस्तेमाल हो सकेगा। कुलपति डॉ एससी दुबे ने कहा कि युवा वैज्ञानिकों को रूस्टिंग कार्यों के अतिरिक्त नवोन्मेषी शोध पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे विज्ञान जगत में उनकी पहचान बने और बढ़े। प्रत्येक वैज्ञानिक को एक-दो वाह्य पोषित शोध

डॉ एके श्रीवास्तव बीएयू पशुपतिनाथ टेंपल मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष बने

रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के अवकाश प्राप्त डीन डॉ एके श्रीवास्तव को सात-सदस्यीय बीएयू पशुपतिनाथ टेंपल मैनेजमेंट कमिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ श्रीवास्तव ने शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में बीएयू में 38 वर्षों तक कार्य किया, 20 वर्ष यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तथा लंबे समय तक पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने दो वर्ष जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में भी कार्य किया। अरसंडे, कक्रे निवासी डॉ श्रीवास्तव कायस्थ क्रांतिकारी विचार मंच की झारखंड राज्य कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बीएयू परिसर में अवस्थित 6-7 दशक प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर की प्रबंधन समिति में सचिव के रूप में पंकज वत्सल तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉ आशीष कुमार चक्रवर्ती, डॉ अरविंद कुमार सिंह, डॉ सुशील कुमार पांडेय तथा डॉ शैलेंद्र कुमार रजक शामिल हैं। पशु चिकित्सा संकाय के सहायक निंत्रक कमिटी के पदेन कोषाध्यक्ष हैं। बीएयू के पशु चिकित्सा संकाय के वर्तमान डीन डॉ आलोक कुमार पांडेय द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है। पूर्व अध्यक्ष डॉ रबीन्द्र भक्त ने इस्तीफा दे दिया था।



परियोजना लाने का प्रयास करना चाहिए। शोध प्रस्ताव समर्पित करते वक्त विभाग के मैंडेट का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पशु-पक्षी प्रक्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन एवं रखरखाव पर जोर दिया। वाह्य विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित आईसीएआर के अवकाशप्राप्त

सहायक महानिदेशक (पशु उत्पादन एवं प्रजनन) डॉ वीके सक्सेना ने कहा कि शोध केवल एकेडमिक उद्देश्य से नहीं करना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या उसके संभावित परिणाम, अनुसंसा और निष्कर्ष को क्षेत्र के सीमित संसाधनों वाले किसानों की

सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कार्यान्वित किया जाना संभव है। शोध का उद्देश्य उत्पादन लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाना होना चाहिए। डॉ सक्सेना ने सुर्गियों की देशी नस्लों के चिह्निकरण, गुण निर्धारण और रजिस्ट्रेशन पर बल दिया। साथ ही

उनके आवसान, प्रबंधन एवं पोषण की बेहतर तकनीक ईजाद करने की जरूरत बताई। डॉ सक्सेना ने बकरियों से बेहतर मांस एवं दूध प्राप्त करने के लिए सिरोही और पलामू नस्ल की बकरियों के संकरण पर शोध करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में वानिकी संकाय के प्रो कोशल कुमार एवं पशु गर्भ विज्ञान विभाग के प्रो संजय कुमार रवि सहित पशु चिकित्सा संकाय एवं वानिकी संकाय के विभागाध्यक्षों ने अपनी शोध उपलब्धियों का ब्योरा रखा। बीएयू के पूर्व कुलपति डॉ जीएस दुबे, पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉ डीके सिंह द्रोण तथा अवकाश प्राप्त डीन डॉ बोके राय ने शोध कार्यों को बेहतर दिशा देने एवं ज्यादा प्रभावी बनाने के संबंध में अपने सुझाव दिये। बैठक का समन्वयन अनुसंधान निदेशक डॉ पी के सिंह ने किया।

रोटरी और सीसीएल के साझा प्रोजेक्ट 'मानस' की सफलता पर आभार समारोह का आयोजन

समाज को कुछ नया देना सीसीएल और रोटरी के मूल में निहित

नव प्रदेश संवाददाता



(सीएसआर) सिद्धार्थ शंकर कहा कि समाज को कुछ नया और बेहतर देना सीसीएल की कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम अपने समाज को नया क्या दें, यही सोच हमारी कंपनी के मूल में निहित है। उन्होंने बताया कि सीसीएल की लाल-लाइली योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 20 छात्र-छात्राओं को आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलगांव में प्रतिवर्ष 12

करोड़ रुपये का सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा नौ गांवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रांची सदर अस्पताल में 50 बेड का आश्रय गृह बनाया जा रहा है। साथ ही नेशनल लॉ कॉलेज के सहयोग से गांवों में मेडिटेशन शिविर आयोजित कर सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं

पहुंचाने के उद्देश्य से सीसीएल द्वारा 10 डायलिसिस मशीनें भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि रोटरी ने भी सेवा के हर क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध किया है। दोनों संस्थाओं की साझेदारी समाज के लिए प्रेरणादायक है। विशिष्ट अतिथि सीसीएल के महाप्रबंधक (वित्त) संजय सिंह ने कहा कि रोटरी की उत्कृष्ट सेवा भावना और कार्यों की विश्वसनीयता के कारण ही



सीसीएल ने रोटरी पर भरोसा जताया और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में सहयोग किया। इस सफर को आगे भी जारी रखा जाएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष ललित त्रिपाठी ने कहा कि रोटरी का मूल उद्देश्य निरु्वाह्य सेवा के माध्यम से

समाज के प्रत्येक वर्ग तक सहायता और उम्मीद पहुंचाना है। सीसीएल जैसी संवेदनशील और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्था के सहयोग से कई जनकल्याणकारी कार्यों को गति मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव सेवा के क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की

एक नजर

प्राइम डे का 10वां संस्करण बना अब तक का सबसे तेज प्राइम डे

रांची। अमेजन इंडिया ने आज घोषणा की कि उसका 10वां प्राइम डे संस्करण अब तक का सबसे तेज प्राइम डे था, जिसमें अमेजन नाउ वाले शहरों में डील पर मौजूद हर दो सामानों में से एक सामान महज कुछ मिनटों में डिलीवर कर दिया गया। प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूटी से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक की श्रेणियों में, ग्राहकों ने अल्ट्राफास्ट डिलीवरी का आनंद लिया, जिसमें उसी दिन होने वाली डिलीवरी में 3 गुना से अधिक का उछाल आया और यह होशियारपुर, उज्जैन और धारवाड़ जैसे टियर 2 और 3 शहरों तक पहुंची। प्राइम के 70 प्रतिशत से अधिक नए साइन-अप टियर 2 और 3 शहरों से आने के साथ, प्राइम वास्टेंट में भारत के लिए एक मेंबरशिप बन गया है। अक्षय साही, व्हाइस प्रेसिडेंट प्राइम एंड कस्टमर फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस, इंडिया एंड इमर्जिंग कंट्रीज, अमेजन ने कहा हम अपने ग्राहकों को बड़ी बचत करने में मदद करना पसंद करते हैं, और प्राइम डे वैल्यू, तेज डिलीवरी, बेहतरीन डील्स, नए लॉन्च और ब्लॉकबस्टर मनोरंजन का अंतिम उत्सव है जो प्राइम मेंबरशिप प्रदान करती है। और प्राइम डे का 10वां संस्करण एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे मनाने में हमें देश भर के अपने सेलर्स, उज्जैन और लाखों ग्राहकों के साथ गर्व महसूस हो रहा है। यह हमारा अब तक का सबसे तेज प्राइम डे था, जहां अमेजन नाउ वाले शहरों में, डील पर मौजूद हर दो में से एक सामान महज कुछ मिनटों में डिलीवर किया गया। हमने छोटे और मध्यम व्यवसायों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी भी देखी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि प्राइम डे हमारे सेलर्स के लिए भी उतना ही बड़ा उत्सव है जितना कि हमारे ग्राहकों के लिए है।

प्राइम के साथ हर दिन बना बेहतर : अमेजन नाउ पर शॉपिंग करने वाले प्राइम मेंबर्स ने 99 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर मुफ्त डिलीवरी का आनंद लिया, साथ ही 1,499 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर 200 रुपये का कैशबैक, सभी ऑर्डर पर जीरो फीस और हर खरीदारी पर सुनिश्चित कैशबैक मिला। प्राइम मेंबर्स ने अमेजन नाउ पर रोमांचक डील्स का लाभ उठाया और अपने प्रोडक्ट्स की कुछ ही मिनटों में डिलीवरी ली। इस प्राइम डे पर अमेजन नाउ के लगभग आधे ऑर्डर ग्रासररी से इतर थे, जिनमें कैमरे, पर्सनल केयर अप्लायंसेज और बहुत कुछ शामिल थे। पिछले प्राइम डे की तुलना में उसी दिन होने वाली डिलीवरी में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई जिसमें प्राइम डे के 4 में से 1 ऑर्डर ग्राहकों के पास उसी दिन पहुंचे। इसके अलावा, प्राइम डे के आधे से अधिक ऑर्डर इवेंट खत्म होने से पहले ही डिलीवर कर दिए गए थे।

श्रीवैष्णवजन के लिए उदया तिथि में एकादशी आज

रांची। अषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नवा योगिनी है। यह बड़े-बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तनों लोको में यह सागरभूत व्रत है। रांची नगर के विदेश्येश्व श्रीलक्ष्मी वेंकटेश्वर (तिरुपति बाल्यजी) मंदिर में अषाढ़ कृष्णपक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई शनिवार को मनाये जायेगे। ईस पवित्रतम व्रत के उपलक्ष्य पर अखिलापाद कंठि ब्रह्माण्डनायक श्रीपद्मावती वल्लभ भगवान् का विशेषपूजा से प्रातः वंदन- तिरुकाराधनम, पूजादि अनुष्ठान संपादन किया जायेगा। नित्याराधन, भोग आरती स्तुति के बाद श्रद्धालु भक्तों के लिए प्रातः 7:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं संध्या 4:00 बजे से 7:00बजे तक मंदिर के पट् खुले रहेंगे। शास्त्रों के मान्यता के अनुसार दशवीं से वेध एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के लघन कर जो एकादशी की व्रत करते है, उसे लक्ष्मी जी साप देकर घर से निकल जाती हैं और उसके वंश की और यश की हानि होती है। जब पूरे दिन और रात में एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातः काल तक चला गया हो तब दूसरे दिन अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का ही उपवास करना चाहिए।

99,639 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से भाजपा का दावा बैनकाब : विजय शंकर नायक

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने कहा कि नेशनल स्ट्रेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान हुए 14 एमओयू और 99,639 करोड़ के प्रस्तावित निवेश ने राज्य में निवेश को लेकर भरोसा का नया संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया कि इससे भाजपा के विकास संबंधी दावों की पोल खुल गई है। नायक ने कहा कि निवेशकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका भरोसा प्रचार नहीं, बल्कि स्थिर नीतियों, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लंबे शासनकाल में राज्य अपेक्षित औद्योगिक विकास हासिल नहीं कर सका, जबकि वर्तमान कांग्रेस-झामुमो गठबंधन सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि झारखंड में बढ़ते निवेशकों के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता एमओयू को धरातल पर उतारकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। भाजपा पर निशाना साधते हुए नायक ने कहा कि विश्व को विकास और निवेश के मुद्दे पर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य की नई पहचान अब निवेश, रोजगार, सुशासन और जनकल्याण से बनेगी तथा विकास की इस प्रक्रिया को दुष्प्रचार से रोका नहीं जा सकता।

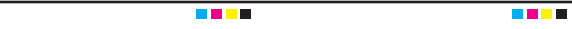
13 और 14 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी

रांची। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 13 और 14 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 17 जुलाई तक राज्यभर में गर्जन, वज्रपात और वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 13 जुलाई को राज्य के उत्तर-पूर्वी, उससे सटे मध्यवर्ती तथा दक्षिण-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 14 जुलाई को उत्तर-पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने तथा वजपात की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। विभाग के मुताबिक, 17 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर वर्षा, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है। लगातार बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव तथा स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है।

साझेदारी समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रही है। प्रोजेक्ट मानस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट चेयरमैन गौरव बागरोय ने कहा कि सेवा तभी सार्थक होती है, जब उसमें संवेदना, विश्वास और सामूहिक सहभागिता का भाव हो। उन्होंने सीसीएल के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि भविष्य में भी दोनों संस्थाएं मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेंगी।

पूर्व गवर्नर अर्जुन खबड़ा ने रोटरी फाउंडेशन एवं उसके उद्देश्य पर चर्चा करते हुए इसके सेवा कार्य एवं पोलियो उन्मूलन की चर्चा की। रोटरी इमेज चेयरमैन प्रवीण

राजगढ़िया ने कहा बैंगलोर के निम्हास के बाद रिनपास में प्रोजेक्ट मानस का होना झारखण्ड एवं आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए बड़ी राहत है। मंच संचालन मुकेश तनेजा एवं धन्यवाद जापन जोगेश गंभीर ने किया। इस अवसर पर संजय कश्यप, क्लब की सचिव शालिनी सिंघानिया, पीडीजी अनिल सिंह, पीडीजी राजीव मोदी, भंडारी लाल, विनोद सरावगी,सुरेश साबु, जी सी सिंह, मनोज तिवारी, शाहिद पॉल, रेखा सिंह, अजय साबु, विनय, अजय वाधवा, डॉ अनंत सिन्हा, रविन्द्र सिंह चड्ढा, अनित अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, चरणजीत वासु, संजय वाधवा, विनोद कुमार, रजत बहल, प्रशांत, दीपक श्रीवास्तव, हितेश भगत, अतुल अग्रवाल, पवन जायसवाल,मनोहर लाल, प्रो अनंत कुमार, इमेज चेयरमैन प्रवीण राजगढ़िया उपस्थित थे।



उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण आवास एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की

लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

नवप्रदेश/गुमला। उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा एवं ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मनरेगा अंतर्गत लंबित देयताओं (पेंडिंग लाइबिलिटीज) की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले दिन तक सभी लंबित प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से एमआईएस में अद्यतन करें। इसके अतिरिक्त



इंजीनी-जी-रामजीर के तहत सभी पंचायतों में अधिकतम मांग सुजित करने का निर्देश दिया गया।उप विकास आयुक्त ने प्रतिदिन दर्ज की गई डिमांड के अनुरूप मस्टर

रोल निर्गत करने तथा एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही ई-केवाईसी एवं जियो-मनरेगा

(आप्टर) से संबंधित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आगामी बुधवार तक उपलब्धि में कम-से-कम पांच प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा।

ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 के ग्रामसभा अपलोडेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की 159 पंचायतों में से 141 पंचायतों में ग्रामसभा अपलोडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कुल 88.68 प्रतिशत है। शेष पंचायतों में 11 जुलाई तक नियमानुसार ग्रामसभा अपलोडेशन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रथम किस्त प्राप्त 3,176 लाभुकों का जिनो-टैगिंग कार्य लंबित है। इस पर सभी

प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आगामी बुधवार तक संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही अबुआ आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर्गत तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गुमला में विशेष नामांकन अभियान शुरू

नवप्रदेश/गुमला। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि गुमला जिले के भरनो एवं घाघरा प्रखंड के चिन्हित 157 विद्यालयों में 07 जुलाई 2026 से 07 सितंबर 2026 तक विशेष नामांकन अभियान संचालित किया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालयों में नामांकित करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनके ठहराव को सुनिश्चित करना है। उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने बताया कि यू-डायस 2025-26 प्रतिवेदन में दर्ज उच्च ड्रॉपआउट दर, कम प्रोवेशन दर तथा नामांकन में कमी जैसे प्रमुख शैक्षणिक सूचकांकों के आधार पर जिले के दो उच्च प्राथमिकता वाले प्रखंडों का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत घाघरा प्रखंड के 99 विद्यालय तथा भरनो प्रखंड के 58 विद्यालय सहित कुल 157



विद्यालयों को विशेष अभियान के लिए चिन्हित किया गया है।उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन कन्विसिंग के माध्यम से एक व्यापक जनअभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, जेएसएलपीएस, नियोजन विभाग, बाल कल्याण समिति तथा अन्य संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वित प्रयास किए जाएंगे, ताकि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खालकों ने कहा सभी स्टेटहोल्डर्स बी आर सी ,सी आर सी,बी पी ओ, एवं एनजीओ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए धरातल पर सक्रिय रूप से कार्य करें, ताकि विद्यालयों में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां ने बताया कि शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का शिशु सदन में तथा 6 से 18 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित

करना आवश्यक है। अभियान के अंतर्गत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो अब तक अनामांकित हैं अथवा किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं और वर्तमान में विद्यालय से बाहर हैं। ऐसे सभी बच्चों को पुनः नामांकित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। बैठक में अपर समाहर्ता राजीव नीरज, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खान, श्रम अधीक्षक धीरेन्द्र महतो, जिला नियोजन पदाधिकारी सत्येन्द्र महतो, जिला श्रम एवं नियोजन पदाधिकारी अनामिका तिवर्ी, जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नेमंती तिग्मा, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधियों सहित सभी संकुल साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी उपस्थित थे।

'हम आपको सुनते हैं' कार्यक्रम में दिखा संवेदनशील प्रशासन का चेहरा

नवप्रदेश/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित जिला प्रशासन के विशेष लोक संवाद कार्यक्रम 'हम आपको सुनते हैं' ने एक बार फिर आम नागरिकों के भरोसे को मजबूत किया। यह कार्यक्रम उस समय बेहद भावुक और संवेदनशील हो उठा, जब चंदनकियारी प्रखंड के भोजुडीह निवासी दिव्यांग कलाई प्रमाणिक को वर्षों पुरानी जरूरत कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। उपायुक्त (डीसी) श्री अजय नाथ झा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उन्हें एक बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। ट्राईसाइकिल प्राप्त होी कलाई प्रमाणिक के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, जिसने पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। 25 आवेदनों पर हुई सीधी सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को एक-एक कर बेहद गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान कुल 25 आवेदन सामने आए, जिन पर क्रमवार सुनवाई की गई। डीसी ने मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों



को निर्देश दिया कि इन सभी मामलों का त्वरित, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों से जुड़े मामलों पर चर्चा और निर्देश दिए गए:- भूमि व राजस्व: अंचल कार्यालयों से जुड़े लंबित जमीनी विवाद। सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था, दिव्यांग व अन्य पेंशन योजनाएं। विकास व उद्योग: बीएसएल, डीपीएलआर और शिक्षा से जुड़े मामले। **अनावश्यक चक्कर कतई बंदरिश नहीं:** डीसी उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कड़े रुख में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध तरीके से निपटारा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, हकिसी भी फरियादी को अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।

डीसी आवास के घेराव के बाद आंदोलन स्थगित, 15 अगस्त तक समाधान का अल्टीमेटम

नवप्रदेश/बोकारो। अपनी विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर शुक्रवार को 'झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा' और 'झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा' के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में विस्थापितों, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने बोकारो DC आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया। सुबह 10 बजे शुरू हुए इस उप प्रदर्शन का नेतृत्व मोर्चा के खिला अध्यक्ष राजदेव माथा ने किया। दोपहर करीब एक बजे प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापितों की समस्याओं से संबंधित मांग-पत्र DC को सौंपा। उख ने इन मांगों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए मोर्चा को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज और समस्याओं का विस्तृत विवरण कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलदल स्थगित कर दिया गया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हजारौरीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 15 अगस्त 2026 तक बोकारो और पूरे झारखंड में विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो राज्यव्यापी व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। मोर्चा के नेताओं, जिनमें केंद्रीय अध्यक्ष विदेशी महतो और केंद्रीय प्रधान सचिव पुष्कर महतो शामिल थे, ने कहा कि उनका संलग्न स्थानीय लोगों, युवाओं और बेरोजगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सभी शेष बचे झारखंड आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना। विस्थापितों की 70 वर्षों से लंबित मांगों के त्वरित और स्थायी समाधान। बोकारो स्टील प्लांट समेत सरकारी और निजी संस्थानों में स्थानीय विस्थापितों के अधिकारों को रोजगार में प्राथमिकता। पलायन रोकने के लिए ठोस रोजगार नीति का निर्माण। जिले के प्रखंडों और अंचलों में व्याप्त भ्रष्टाचार व घूसखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध।

गुम हुआ मोबाइल बरामद, सेक्टर-12 थाना पुलिस ने मालिक को लौटाया

नवप्रदेश/बोकारो। सेक्टर-12 थाना पुलिस ने तकनीकी शाखा के सहयोग से गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया। इस संबंध में सेक्टर-12 थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर-12/डी. क्वार्टर संख्या-2013 निवासी राजेश कुमार (पिता स्व. आनंदी मंडल) ने 15 जून 2026 को अपना मोबाइल फोन गुम होने की लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर तकनीकी शाखा की मदद से जांच की गई। जांच के दौरान आवेदक का मोटोरोला (मॉडल 02343-5) मोबाइल बरामद कर लिया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार 9 जुलाई 2026 को मोबाइल उसके वास्तविक मालिक राजेश कुमार को विधिवत सौंप दिया गया। मोबाइल वापस मिलने पर राजेश कुमार ने बोकारो पुलिस और तकनीकी शाखा का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना में सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

एसआईआर-2026: बोकारो में डीसी-एसपी ने लिया कार्यों का जायजा, मतदाताओं से की शत-प्रतिशत भागीदारी की अपील



नवप्रदेश/बोकारो। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ह्रद्विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026ह्द्व अभियान की समीक्षा हेतु शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) श्री अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्री नाथ सिंह मीना ने संयुक्त रूप से विभिन्न सेक्टरों में चल रहे डिजिटाइजेशन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ईआरओ सह एसडीओ (वास) श्रीमती प्रांजल दांडा भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के दौरान डीसी-एसपी ने सेक्टर-9बी स्थित रन विजय स्मारक उच्च विद्यालय के बूथ संख्या 208, 209 और 210 का दौरा किया। अधिकारियों ने बीएलओ (इछड़) से गणना प्रपत्रों के वितरण और उनके डिजिटाइजेशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रविवार तक हर हाल में शत-प्रतिशत प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों ने स्वयं सेक्टर-9ए स्थित क्वार्टर नंबर 1476 में मतदाता श्री प्रयाग दे से मुलाकात की। उन्होंने न केवल स्वयं गणना प्रपत्र भरवाया, बल्कि मौके पर ही उसका डिजिटाइजेशन भी सुनिश्चित कराया। यह प्रयास आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। डीईओ सह डीसी अजय नाथ झा ने कहा, एसएसआईआर-2026 केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। सभी मतदाता इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें। संयुक्त टीम ने सेक्टर-01बी/सी (दीक्षा संस्थान), सेक्टर-9बी, सेक्टर-8ए, सेक्टर-3डी और सेक्टर-3ए स्थित बूथों पर भी कार्य की समीक्षा की। विशेष रूप से बूथ संख्या 245, 325, 326, 298 सहित 286 से 289 तक के बूथों पर कार्य की निगरानी की गई। इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रेमचंद सिन्हा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पेटरवार में महिला से 50,000 की छिनतई करने वाले बुलेट सवार दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, भेजा जेल

नवप्रदेश/पेटरवार (बोकारो)। पेटरवार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में सक्रिय बुलेट सवार दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से छिनतई में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल और लूटी गई रकम में से 23,000 नगद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में से एक का पुराना और लंबा अपराधिक इतिहास रहा है। बतौी 8 जुलाई 2026 को कोनारबेड़ा निवासी मंजू देवी (पति स्व. जगदीश महतो) पेटरवार बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 निकासकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान जाराटांड व्यापार मंडल भवन के पास एक



सुनसान जगह पर बुलेट सवार दो अज्ञात अपराधियों ने उनका पीछा कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पेटरवार थाना में कांड संख्या 114/26 (धारा-304(2) BNS) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस

पदाधिकारी बेरमो, तेनुघाट के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मानवीय एवं तकनीकी इनपुट्स के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छिनतई में शामिल दोनों अपराधियों को धर दबोचा। **गिरफ्तार अपराधियों के नाम:** दिलीप तिवारी (उम्र करीब 38 वर्ष), पिता- स्व. दशरथ तिवारी, निवासी- सहरजोरी, थाना-

चंदनकियारी, जिला- बोकारो। ब्रजेश कुमार शर्मा (उम्र करीब 32 वर्ष), पिता- अंबुज शर्मा, निवासी- सहरजोरी, थाना-चंदनकियारी, जिला- बोकारो। **पृष्ठताछ में कबूला एक और बड़ा अपराध** पुलिस की कड़ी पृष्ठताछ में दोनों अपराधियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जाराटांड के पास महिला से 50,000 की छिनतई उन्होंने ही की थी। इसके अलावा, दोनों ने यह भी कबूल किया कि बीते 9 जून 2026 को पेटरवार गेस्ट हाउस के सामने से इसी बुलेट मोटरसाइकिल का उपयोग कर उन्होंने 49,000 की लूट की एक और घटना को अंजाम दिया था।

एक नजर

विकास बंद तो तालाबंदी फिर 24 घंटे में ही आंदोलन समाप्त खोला ताला

नवप्रदेश/गुमला। आम जनता अब बेवकूफ नहीं है और आम जनता जानती है कि विधानसभा हो या लोकसभा सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में तकरार होने आम बात है और लोग भी देखते आए हैं कि सत्ताधारी और विपक्षियों के नोक-झोंक में पॉलियामेंट से लेकर विधानसभा में काम बाधित होता आया है लेकिन गुमला नगर परिषद में हुए आम चुनवाों से चयनित हुए जन प्रतिनिधियों में पक्ष और विपक्ष ऐसी कोई बात नहीं फिर भी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। और अखाबारों के माध्यम से जनता के बीच



जगजाहिर हो चुका है कि कुछ-न-कुछ राजनीति चली जा रही है। बट का गठन के बाद प्रारंभ में कमीशन खोरी का आरोप प्रत्यारोप के बाद नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में वाई परिषदों के साथ खोला गया मोर्चा और विकास के काम में विधायक के अच्छे के बाद सियासी पारा चढ़ने के बाद नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरूवार को किए गए तालाबंदी विकास नहीं तो तालाबंदी का आंदोलन और फिर 24 घंटे के अंदर ही आंदोलन का रास्ता तैयार करने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर परिषद कार्यालय में किए गए तालाबंदी आंदोलन को ताला खोलकर स्वयं सुख्खियों में आ गए हैं आंदोलन वापसी का दुहाई यह दी जा रही है कि आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए आंदोलन समाप्त किया जा रहा है। यहां बताते चले कि गुमला नगर परिषद में जो भी चल रहा है यह सिर्फ अखाबारों में सुर्खियों बढोत्रने से ज्यादा कुछ नहीं है। नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी आंदोलन को लेकर एडवोकेट खुर्शीद आलम में भी फेसबुक पर कहा है कि यह संवैधानिक आंदोलन नहीं है और विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए किया गया जो कि जनप्रतिनिधियों द्वारा आम नागरिकों को होने वाले छोटे-छोटे काम जैसे की जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र मकान टैक्स आदि काम को रोकने के लिए किया गया तालाबंदी कानूनी रूप से वैध नहीं है बिना सूचना दिए तालाबंदी का रास्ता तैयार करना इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और वैसे लोगों पर कनूनी कार्रवाई के लिए विधायक को आगे आने की जरूरत है।

बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात

नवप्रदेश/बोकारो। बोकारो विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती श्वेता सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक के दौरान झारखंड और खासकर बोकारो क्षेत्र के जनसरोकारों, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों तथा जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक धारदार बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान विधायक श्वेता सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई दी। उन्होंने खड़गे जी को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु जीवन की कामना की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक श्रीमती श्वेता सिंह ने कहा कि आदरणीय खड़गे जी के अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देशहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश और राज्य के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे संगठन जनहित के मुद्दों पर और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बैठक में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। विधायक ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य संगठन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करना है।

गुमला में मध्यस्थों एवं एलएडीसी की संयुक्त बैठक आयोजित

नवप्रदेश/गुमला। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), गुमला के तत्वावधान में मध्यस्थों एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक का

आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकर, गुमला श्री अजीत कुमार सिंह ने की।बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकर, गुमला के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय ने न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए मध्यस्थता की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मध्यस्थों से पूरी निष्पक्षता एवं समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं को भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील एवं उत्तरदायी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मध्यस्थता की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, राष्ट्रीय विधिक सहायता उपलब्ध नालसा की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा सह स्त्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित

नवप्रदेश/गुमला। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय अनुकंपा सह स्त्रीनिंग समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में उप विकास आयुक्त,

गुमला अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्त्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में विभिन्न प्रस्तावों एवं मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सामान्य अनुकंपा के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा उग्रवादी हिंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।साथ ही, एम०ए०सी०पी०एस० के तहत विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रोन्नति संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया गया। सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामलों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रोन्नति संबंधी प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

15 जुलाई से पहले हर पंचायत में एसआईआर अभियान तेज करने का निर्देश

नवप्रदेश/बरिया (गुमला)। प्रखंड कांग्रेस कमेटी बरिया की बैठक शुक्रवार को कानबीर स्थित विवाह मंडप में प्रखंड अध्यक्ष विकास साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की गई तथा 15 जुलाई को प्रत्येक पंचायत में बैठक आयोजित कर अभियान को गति देने का निर्णय लिया गया।बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं सिसई विधानसभा प्रभारी रोहित उरांव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव रोशन बरवा तथा जिला महासचिव सह बरिसिया प्रखंड सांसद प्रतिनिधि सुशील कुमार होता उपस्थित थे। इस अवसर पर रोहित उरांव ने कहा कि एस आई आर केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरवाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।





राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव

अयोध्या में श्रीराम मंदिर केवल एक भव्य धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन, विशाल दान-राशि के प्रबंधन तथा मंदिर परिसर के लगातार विस्तार को देखते हुए अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और पेशेवर बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी दिशा में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम माना जा सकता है। अब तक मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से निभाई जा रही थी, लेकिन बढ़ती गतिविधियों और व्यवस्थागत चुनौतियों को देखते हुए एक ऐसे पेशेवर अधिकारी की जरूरत थी, जो पूरे प्रशासन का प्रभावी संचालन कर सके। सीईओ को मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक प्रबंधन, कर्मचारियों की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव जैसी व्यापक जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। इससे कार्यों में स्पष्ट जवाबदेही तय होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बन सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का पारदर्शी प्रबंधन है। श्रद्धालुओं द्वारा दी जाने वाली राशि करोड़ों रुपये में होती है, इसलिए आधुनिक अकाउंटिंग प्रणाली, नियमित ऑडिट तथा वित्तीय विशेषज्ञों की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। यदि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होगी तो श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा किसी प्रकार की अनियमितता या विवाद की संभावना भी न्यूनतम रह जाएगी। दूसरी बड़ी चुनौती प्रतिदिन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में दर्शन व्यवस्था, भौड़ नियंत्रण, सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं, पार्किंग, यातायात और आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं का कुशल संचालन अत्यंत आवश्यक है। सीईओ यदि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हैं तो श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सकेगा। करीब ढाई हजार कर्मचारियों के कार्यों का समन्वय, निर्माण कार्यों की निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का रखरखाव भी किसी बड़े संस्थान की तरह पेशेवर प्रबंधन की मांग करता है। यही कारण है कि मंदिर प्रशासन में यह बदलाव केवल पद सुजन नहीं, बल्कि आधुनिक संस्थानगत व्यवस्था की ओर बढ़ाया गया कदम है। हालांकि, केवल पद का सुजन पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक है कि सीईओ का चयन योग्यता, ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव और निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। साथ ही उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नियमित समीक्षा और जन्म-जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। यदि इन सिद्धांतों का पालन किया गया तो श्रीराम मंदिर की व्यवस्था देश के अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थानों के लिए भी एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल बन सकती है। आस्था और आधुनिक प्रबंधन का यह संतुलित समन्वय ही राम मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं के विश्वास को लंबे समय तक सुदृढ़ बनाए रखेगा।

सुधा

चेतना को जान लोगे, तो मृत्यु का डर नहीं रहेगा, न जीवन बोझ लगेगा

सुंदरचंद ठाकुर

एक प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों दोनों को उलझाता रहा है। पहले क्या आया? चेतना या शरीर? अधिकतर लोग बिना सोचे कहते हैं कि पहले शरीर आया, फिर उसमें चेतना जागी। पर आधुनिक क्वांटम भौतिकी और हजारों साल पुराना वेदांत, दोनों एक ही चौंकाने वाला उत्तर देते हैं। पहले चेतना है। शरीर उसके बाद आता है। क्वांटम भौतिकी का सबसे रहस्यमय सिद्धांत है – observer effect। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब तक कोई किसी कण को देख नहीं रहा होता, वह कण एक साथ अनेक स्थानों पर हो सकता है। एक संभावना की अवस्था में। जैसे ही कोई उसे देखता है, वह एक निश्चित स्थान पर प्रकट हो जाता है। अर्थात देखने वाले की चेतना ने उस कण की वास्तविकता तय की। यह केवल प्रयोगशाला का नतीजा नहीं है बल्कि यह एक गहरा सत्य है। वास्तविकता एक के बिना अस्थुरी है। चेतना पहले है, पदार्थ बाद में। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकशास्त्री मैक्स प्लांक ने कहा था कि चेतना ही सब कुछ का मूल है। पदार्थ उससे जन्मा हुआ है। यह वही बात है, जो उपनिषद कहते हैं - पहले ब्रह्म था, फिर सृष्टि हुई। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आप साफ़ पानी देख रहे हैं। उस पानी में पहाड़ हैं, नदियां हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं। सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लगता है। पर वह सब कहाँ से आया? आपकी चेतना से। चेतना ने पूरा संसार रच दिया। और जब नौद टूटी, तो सब विलीन हो गया। वेदांत कहता है कि यह जो हम जागते हुए जीवन जी रहे हैं, वह भी उसी तरह चेतना का एक विस्तार है। और यहाँ निसर्गदंत महाराज का वह महान बोध आता है जिसने उनका जीवन बदल दिया। उनके गुरु ने उनसे केवल एक बात कही-तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम वह चेतना हो जिसमें सब कुछ हो रहा है। और निसर्गदंत ने इसी एक वाक्य को पकड़ लिया। वे बस यहीं देखते रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? और उस प्रश्न में ढूँढते-ढूँढते एक दिन उत्तर मिला – I Am That! मैं वह हूँ। वह परम चेतना जो सबकी साक्षी है। इसे ऐसे समझिए। आप टीवी देख रहे हैं। पर्दे पर दृश्य आते जाते हैं-कभी खुशी, कभी दुःख, कभी युद्ध, कभी प्रेम। पर पर्दा हमेशा वैसे ही रहता है। शांत, निर्मल, अप्रभावित। निसर्गदंत कह रहे थे - तुम पर्दा हो, दृश्य नहीं। दृश्य आते जाते हैं। पर्दा यानी चेतना सदा बनी रहती है। यही I Am That का सार है। मैं वह हूँ जो सब देख रहा है। जो सब अनुभव कर रहा है, पर जो किसी अहंकार से बंधा नहीं है। तो शरीर पहले नहीं आया। चेतना पहले थी और शरीर उसी में प्रकट हुआ, जैसे सपने में पात्र प्रकट होते हैं। क्वांटम भौतिकी यही कह रही है। वेदांत यही कहता आया है। और निसर्गदंत ने इसे जोकर दिखाया। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाए, उस दिन न मृत्यु का डर रहता है, न जीवन का बोझ। क्योंकि तब पता चलता है कि तुम वह हो जो कभी मरता नहीं।



योगेश कुमार गोयल

यहां 1994 में महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 3.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.2 रह गई थी यानी सामान्य के करीब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ने के बाद से गिरनी शुरू हो जाएगी और 2100 तक पहुंचते-पहुंचते सामान्य प्रजनन दर केवल 1.3 ही रह जाएगी।



डॉ. प्रियंका सीरथ

लोकतंत्र में असहमति विरोध नहीं होती, बल्कि नीति निर्माण को बेहतर बनाने का माध्यम होती है। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए भी उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी प्रकार सीटों की संभावित वृद्धि का समर्थन या विरोध भी तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आग्रहों के आधार पर। अंततः भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जहां प्रतिनिधित्व भी बढ़े, जवाबदेही भी मजबूत हो और सार्वजनिक संसाधनों का वितेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित हो।



डा. मयंक चतुर्वेदी

भारतीय परंपरा में गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि की प्रार्थना, शांति मंत्र को समस्त विश्व के कल्याण की कामना और सरस्वती वंदना को ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इनका मूल भाव नैतिक और मानवीय है। इन्हें सिर्फ संकीर्ण धार्मिक दृष्टि से देखना भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यापकता को सीमित कर देना होगा।

अभिव्यक्ति

महिला आरक्षण, लोकसभा सीटों का विस्तार व लोकतंत्र की कसौटी

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी समावेशी भावना है। यह व्यवस्था केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का संवैधानिक वादा भी है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इसी वादे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम रही है। इसलिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य माना जाता है। यह केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी प्रश्न है। लेकिन महिला आरक्षण की इस ऐतिहासिक पहल के साथ एक नई बहस भी जन्म ले चुकी है। क्या महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में भारी वृद्धि आवश्यक है? क्या मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से भी गंभीर है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संभावित वृद्धि दो अलग-अलग विषय हैं। महिला आरक्षण का संबंध निर्वाचित सीटों के आरक्षण से है, जबकि लोकसभा की सीटों का विस्तार भविष्य के परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़ा हुआ विषय है। फिर भी आम नागरिक के मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यदि आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, तो क्या इसके लिए संसद का आकार बढ़ाना अनिवार्य है? लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल अधिक सांसद होना नहीं है। लोकतंत्र की सफलता इस बात से मापी जाती है कि जन प्रतिनिधि कितने उत्तरदायी हैं, संसद में कितनी गंभीर बहस होती है, कानून कितनी गुणवत्ता से बनते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कितना प्रभावी ढंग से होता है। यदि केवल संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत होता, तो दुनिया के सबसे बड़े संसद वाले देश स्वतः सबसे बेहतर लोकतंत्र भी होते। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।

देश में आज भी लाखों लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, कृषि संकट और आधारभूत सुविधाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि संसद की संख्या बढ़ती है, तो जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे शासन अधिक प्रभावी होगा या केवल सरकारी खर्च बढ़ेगा? प्रत्येक सांसद के साथ वेतन, कार्यालय, कलेंडर, आवास, यात्रा, सुरक्षा, संसदीय संसाधन और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी



जुड़ा होता है। इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वित्तीय निर्णय भी है। हालांकि इस विषय पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अकसर सार्वजनिक चर्चा में सांसदों के वेतन और सरकारी खर्च के बारे में कई दावे किए जाते हैं, जिनके वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी आर्थिक तर्क को प्रमाणित सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विमर्श तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अतिशयोक्ति पर नहीं। इसलिए किसी भी आर्थिक तर्क को प्रमाणित कि बिना संवैधानिक गारंटी के राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट नहीं देंगे। पिछले सात दशकों का अनुभव भी यही बताता है कि अधिकांश दल चुनावों में महिलाओं को सीमित अवसर देते रहे हैं। इसलिए आरक्षण आवश्यक है। यह तर्क मजबूत और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। दूसरी ओर एक चिंता यह भी व्यक्त की जाती है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम पायदान की महिलाओं तक पहुंचेगा? भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना आज भी अत्यधिक संसाधन-आधारित प्रक्रिया है। ऐसे में संभावना रहती है कि टिकट वितरण में राजनीतिक परिवारों, उन्माधुशाली नेताओं, आर्थिक रूप से सक्षम उन्मादवाजों अथवा पहले से प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले। यदि ऐसा होता है, तो ग्रामीण, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाएगा। यह चुनौती केवल महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की समग्र संरचना की चुनौत है। जब तक राजनीतिक दल अपने संतानात्मक ढांचे में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर नहीं देंगे, तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण से अपेक्षित परिवर्तन सीमित रह सकता है। वास्तविक महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल संसद तक पहुंचाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना भी है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। लगभग सभी दल महिला सम्मान और

महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित दिखाई देती है। यदि राजनीतिक दल स्वयं अपनी कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ, तो लोकतांत्रिक संस्कृति अधिक मजबूत होगी। लोकसभा की सीटों में संभावित वृद्धि का एक दूसरा आयाम संघीय संतुलन भी है। परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन हो सकता है। इससे विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन प्रभावित होने की संभावना पर भी विशेषज्ञ चर्चा करते रहे हैं। इसलिए यह केवल संसद की संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था का भी विषय है। ऐसे निर्णय व्यापक राष्ट्रीय सहमति और गंभीर विमर्श के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की एक और चुनौती है—जन प्रतिनिधियों के प्रति जनता का घटना विश्वास। संसद में व्यवधान, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, विधेयकों पर सीमित चर्चा और चुनावी राजनीति का बढ़ता प्रभाव लोगों के मन में यह प्रश्न पैदा करता है कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम कर रही हैं? यदि जनता पहले से ही प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठा रही है, तो संख्या बढ़ाने से पहले जवाबदेही बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में गुणवत्ता, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि संसद की कार्यवाही अधिक प्रभावी हो, संसदीय समितियाँ बेहतर ढंग से काम करें, सांसद अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें और कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने, तो जनता का विश्वास स्वतः बढ़ेगा। केवल अधिक सांसद होने से लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी नहीं हो जाता। महिला आरक्षण को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से संसद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय और परिवार से जुड़े विषयों पर अधिक संवेदनशील बहस होने की संभावना

हिन्दू धर्म आधारित संस्कारों की शिक्षा पर न्यायिक मुहर



मूल्य आधारित शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग मानती है। ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रयास उसी व्यापक नीति का विस्तार माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 28, 29 और 30 का उल्लंघन बताते हुए इसे धार्मिक शिक्षा का स्वरूप देने का प्रयास किया। उनका तर्क था कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे मंत्रों का वाचन अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को असहज कर सकता है। यह एक संवैधानिक प्रश्न था, जिसका उत्तर सिर्फ भावनाओं के आधार पर देना संभव नहीं था। यहाँ पर उच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 28(1) का आशय राज्य पोषित संस्थानों में किसी विशेष धर्म के कर्मकांड, पूजा-पद्धति अथवा धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा को रोकना है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नैतिक शिक्षा, नागरिक कर्तव्यों, सामाजिक समरसता और चरित्र विद्यालयों में जो व्यवस्था लागू की, उसका पोषित वैधता विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक वेतना और सैतक मूल्यों से जोड़ना था। राष्ट्रीय आदेश नीति-2020 भी स्पष्ट रूप से भारतीय ज्ञान प्रणालियों, स्थानीय परंपराओं और

जा रहा हो। महत्वपूर्ण यह भी है कि आदेश में किसी छत्र के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए यह निर्णय भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के बीच कृत्रिम टकराव पैदा करने वाली सोच पर भी अप्रत्यक्ष प्रश्नचिह्न लगाता है। भारतीय परंपरा में गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि की प्रार्थना, शांति मंत्र को समस्त विश्व के कल्याण की कामना और सरस्वती वंदना को ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इनका मूल भाव नैतिक और मानवीय है। इन्हें सिर्फ संकीर्ण धार्मिक दृष्टि से देखना भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यापकता को सीमित कर देना होगा। इस निर्णय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति तकनीकी दक्षता से आगे समग्र व्यक्तिव निर्माण पर बल देती है। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और संवैधानिक कर्तव्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बताया गया है। यदि विद्यालय बच्चों को केवल परीक्षा पास करने की मशीन बना दें और उनके भीतर अनुशासन, करुणा, कृतज्ञता, राष्ट्रबोध तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास न हो, तो शिक्षा अस्थुरी रह जाएगी। आज जब समाज अनेक सामाजिक व्युत्पत्तियों, बढ़ती हिंसा, नशे की प्रवृत्ति, डिजिटल च्युनन और नैतिक संकट का सामना कर

रहती है। विश्व के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इसलिए महिला प्रतिनिधित्व का विस्तार लोकतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहे। महिलाओं को केवल चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं, बल्कि संसदीय समितियों, मंत्री परिषदों, नीति आयोगों और राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में भी समान अवसर मिलें। तभी आरक्षण अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। यदि वर्तमान 543 सीटों के भीतर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो यह विकल्प भी गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च की आवश्यकता भी कम होगी। यदि यह भविष्य में परिसीमन के संवैधानिक प्रावधानों के कारण सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उसके औचित्य, आर्थिक प्रभाव और लोकोतांत्रिक लाभों पर भी सरकार को स्पष्ट और पारदर्शी संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति विरोध नहीं होती, बल्कि नीति निर्माण को बेहतर बनाने का माध्यम होती है। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए भी उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी प्रकार सीटों की संभावित वृद्धि का समर्थन या विरोध भी तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आग्रहों के आधार पर। अंततः भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जहां प्रतिनिधित्व भी बढ़े, जवाबदेही भी मजबूत हो और सार्वजनिक संसाधनों का वितेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित हो। महिलाओं की भागीदारी को समृद्ध बनाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि लोकतांत्रिक सुधार जनता के विश्वास, आर्थिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ें। महिला आरक्षण का उद्देश्य अधिकार देना है, न कि केवल संख्या बढ़ाना। यदि यह उद्देश्य मौजूद व्यवस्था के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता है, तो उस विकल्प पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। और यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अपरिहार्य हो, तो उसके पीछे के कारण, लाभ और वित्तीय परभाव जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखे जाने चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास है, और वह विश्वास तभी मजबूत होता है जब निर्णय संवाद, तर्क और उत्तरदायित्व के साथ लिए जाएं। (लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

विश्व जनसंख्या दिवस : रुकना चाहिए जनसंख्या विस्फोट

जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम ऊंट के घुंटे में जीरा ही साबित हुए। देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से जनसं भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल हो ही नहीं सकती थी। आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 प्रतिशत आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा

होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लाश्व की प्राप्ति संभव नहीं है। देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। देश को 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी



लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पतियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों के सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।

जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती रही। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर

दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन समाजिक जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों की आबादी नियंत्रण नीति का सामना करना पड़ा था, वह और गहरा होने की उम्मीद थी, इसीलिए चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा। जहां तक भारत की बात है तो यहां 1994 में महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 3.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.2 रह गई थी यानी सामान्य के करीब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ने के बाद से गिरनी शुरू हो जाएगी और 2100 तक पहुंचते-पहुंचते सामान्य प्रजनन दर

केवल 1.3 ही रह जाएगी। इसका अर्थ है कि तब अधिकांश परिवारों में केवल एक ही बच्चा होगा और भारत उसी स्थिति में खड़ा होगा, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चीन खड़ा हुआ और उस विचार सात वर्षों में दो बार अपनी जनसंख्या नीति में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे कानूनों के जरिये जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को व्यावहारिक नहीं माना जा रहा बल्कि इसके लिए उपाय-धमकाने वाले कानूनों के बजाय लोगों में जागरुकता पैदा किया जाना सबसे जरूरी है। बगैर कड़े कानूनों के देश के ऐसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, जहां साक्षरता दर ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीब महिलाओं की प्रजनन दर करीब 3.2 है जबकि सम्पन्न महिलाओं में यह दर केवल 1.5 पाई गई है। इसी प्रकार अनपढ़ महिलाओं के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं जबकि शिक्षित महिलाओं में यह संख्या औसतन 1.7 है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जनसंख्या विस्फोट का सीधा संबंध सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों से जुड़ा है। शिक्षा के अभाव में ही देश की बड़ी आबादी को छोटे परिवार के लाभ को लेकर जागरूक नहीं किया जा सका है। (लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

इंजीनियरिंग में बेस्ट ऑप्शंस

स्टूडेंट्स के बीच इंजीनियरिंग हमेशा से हॉट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि बैचलर

ऑफ इंजीनियरिंग के बाद करियर के कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। कोर्स

कंप्लीट करने के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर में

शानदार जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा

रहे हैं, तो जानें यहां आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं..

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 12वीं में साइंस सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स/ बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए। अधिकतर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इंजीनियर के बीई/बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करती है। इस कोर्स की अवधि चार वर्ष की होती है। इसमें डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है। कुछ संस्थानों में एडमिशन बारहवीं के अंक के आधार पर भी होता है। आज इस फील्ड में अवसर भी कम नहीं है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स प्रोडक्शन, सेल्स, मैनेजमेंट, रिसर्च आदि फील्ड में जॉब की तलाश कर सकते हैं।

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग



12वीं साइंस (मैथ्स) के स्टूडेंट्स बीई/बीटेक एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या एयरोनॉटिक्स में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। विभिन्न कॉलेजों और आईआईटीज में एयरोनॉटिक्स में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स उपलब्ध है। कई पॉलिटेक्निक्स द्वारा एविएशन में डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। देश में कुछ संस्थान एविएशन में पोस्ट ग्रेजुएट (एमटेक) और डॉक्टोरल प्रोग्राम (पीएचडी) भी कराते हैं। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का बीई/ बीटेक कोर्स चार साल का होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्स की अवधि दो-तीन साल होती है। एयरोनॉटिकल इंजीनियर गवर्नमेंट और प्राइवेट एयरलाइंस में जॉब की तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा, नेशनल एयरोनॉटिकल लैब, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, इसरो आदि में भी जॉब पा सकते हैं।

ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग

इन दिनों ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। आप आईआईटी (गुवाहाटी) से बीटेक इन डिजाइनिंग (चार वर्षीय) का कोर्स कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) अहमदाबाद, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में चार वर्षीय प्रोग्राम ऑफर करती है।

इन सभी कोर्स में 12वीं (पीसीएम) के बाद जेईई मेन्स और एडवांस कालिफाई करके एडमिशन लिया जा सकता है। आईआईटी, दिल्ली से इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री (दो वर्षीय) हासिल कर सकते हैं। आईआईटी, कानपुर भी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में दो वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स कराती है। इसके अलावा, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, आईआईटी-मुंबई से इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री (दो वर्षीय) प्राप्त कर सकते हैं।

जेनेटिक इंजीनियरिंग

इस कोर्स में एंटी के लिए 12वीं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स से पास होना जरूरी है। इस समय अधिकतर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अलग से कोर्स ऑफर नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी पढ़ाई बायोटेक्नोजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में सहायक विषय के रूप में होती है। बायोटेक्नोलॉजी के अर्डर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। गेजुएट कोर्स, बीई/बीटेक में एंटी प्रवेश परीक्षा के आधार पर होती है। जेनेटिक इंजीनियर के लिए भारत के साथ-साथ विदेश में भी जॉब के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मेडिकल और फार्मास्युटिकल कंपनी, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट और गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर में जॉब हासिल कर सकते हैं। टीचिंग को भी करियर ऑप्शन के रूप में आजमाया जा सकता है।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट को जेईई या फिर स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाले इंजीनियरिंग एग्जाम को कालिफाई करना जरूरी है। 12वीं साइंस के स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविजन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव्स से संबंधित इंडस्ट्रीज में इसकी खूब मांग है। इसके अलावा, एटमी प्लांट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर आदि के डिजाइन और डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर की अहम भूमिका होती है।

फायर इंजीनियरिंग

फायर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए साइंस सब्जेक्ट्स से बारहवीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा, इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए कई संस्थान नेशनल लेवर पर एंट्रेंस एग्जाम और साक्षात्कार आदि भी आयोजित करते हैं। फायर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्स के दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी जाती है। इन कोर्सेज में फिजिकल फिटनेस के मार्कस भी जोड़े जाते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जेड एस लाकड़ा के मुताबिक, फायर इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में



काफी संभावनाएं हैं। इस फील्ड में जुड़े प्रोफेशनल्स रेलवे, एयरफोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओएनजीसी, माइंस, रिफाइनरिज, पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स आदि में जॉब की तलाश कर सकते हैं।

कंप्यूटर साइंस

कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने के लिए मैथ्स और साइंस (फिजिक्स, केमेस्ट्री) में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस ब्रांच में बीई या बीटेक करने के बाद पोस्टग्रेजुएशन यानी एमई/एमटेक किया जा सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए देश-विदेश दोनों जगहों पर अच्छी संभावनाएं हैं। ये सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करते हैं। इस फील्ड से जुड़े लोगों को सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी कंपनियों में जॉब मिलती है। कंप्यूटर इंजीनियर अपनी टीम के साथ मिलकर मैथ और साइंस का प्रयोग करके कंप्यूटर को डिजाइन और डेवलप करते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर के पुजरे के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को हार्डवेयर इंजीनियर कहा जाता है और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के साथ काम करते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है।

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग

इन दिनों पेट्रोलियम इंजीनियर्स की काफी डिमांड है। अन्य इंजीनियरिंग ब्रांच की ही तरह पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का 12वीं साइंस (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स) से पास होना जरूरी है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए जेईई पास करना जरूरी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपी आदि में जॉब की तलाश की जा सकती है।

माइनिंग इंजीनियरिंग

माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 12वीं पास होना जरूरी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, आईपीसीएल, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आदि में जॉब की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसके अलावा, रिसर्च और टीचिंग में भी काफी स्कॉप है।

आफिस और आपका व्यवहार

ऑफिस में कभी काम को कल पर

टाल कर, तो कभी काम ज्यादा होने पर

छुट्टी ले लेना जैसी आदतें पुरुषों में ही

नहीं, बल्कि महिला कर्मचारियों में भी

पाई जाती हैं। उन्हें तो शायद यह

महसूस भी नहीं होता कि उनकी यह

आदत धीरे-धीरे उनकी ही परफार्मेंस

पर भारी पड़ते हुए उन्हें बॉस की नजरों

में गैर-जिम्मेदार ठहराती जा रही है।

महिलाएं अक्सर दूसरों के सामने यह राग अलापती हैं कि वे तो मजे की नौकरी कर रही हैं। ऐसी बातें जब बॉस के कानों में पहुंचती हैं, तो वह निल-परफार्मेंस के साथ सहज ही आपकी तुलना कर लेता है। यही कारण है कि जब प्रमोशन की बात आती है तो कई बार आपके जूनियर बाजी मार जाते हैं। ऐसी कई गलतियां हैं, जिनकी आदी हो चुकी महिला कर्मचारी इन्हें अपनी आदत बना लेती हैं। यदि आप में भी कोई ऐसा अवगुण है तो उसे समय रहते ही सुधार लेना आवश्यक है।

अपनी गलती दूसरों के सिर न मढ़ें

अपनी गलती को छिपाने वाले तथा बॉस की नजरों में अच्छी इमेज साबित करने वाले लोग हर जगह होते हैं। ऐसे लोग अपनी गलती दूसरे के सिर मढ़ कर बच निकलना चाहते हैं, परंतु अपनी इस आदत के कारण दूसरों की परेशानी की वजह बन जाते हैं। यदि आप में भी यह आदत है तो इसे सुधार लेना ही बेहतर है। हो सकता है कि आरंभ में अपनी गलती मानते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन यकीन मानें कि उसे छिपाने में आपको कहीं ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अपने किसी कुलीग के सिर गलती मढ़ने की कोशिश हर बार कामयाब नहीं हो सकती और गलती साबित हो जाने पर वह स्थिति अधिक कष्टदायक हो सकती है।



रोज की बहानेबाजी तौबा-तौबा

कई बार आप सुबह उठती हैं और काम पर जाने का मन नहीं हो रहा या बच्चों ने घूमने की फरमाइश कर दी तो तुरंत फोन कर बॉस से पेट दर्द, सिरदर्द या किसी और बीमारी का बहाना बना कर आप लीव ले लेती हैं। छुट्टी लेना तो आपका अधिकार है और उस समय आप अभिनय में कलाकारों को भी मात दे देती हैं। कुछ दिन की छुट्टी चाहिए तो मैडीकल सर्टीफिकेट देकर लंबी छुट्टी ले लीं परंतु ऐसी बहानेबाजी आपके दूसरे कुलीम्स का वर्क प्रेशर बढ़ा देती है। कभी यह सोचा है कि आपकी इस आदत के चलते आप अपने सहयोगियों का ही नहीं, बल्कि अपने बॉस का भी विश्वास खोने लगती हैं, क्योंकि वह आपको जिम्मेदारी का काम या ओहदा देने से कतराने लगते हैं।

व्यवहार हो संतुलित

किसी ने आपके काम पर उंगली उठाई या फिर आपको किटीसाइज किया तो आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में लाल-पीली होकर सामने वाले पर बरस उठती हैं या फिर आप सामने वाले की कही गलत बातों को भी चुपचाप सुन स्वयं में ही सिमटे हुए वहां से उठ कर चल देती हैं। प्रोफेशनल नजरिए से देखा जाए तो दोनों तरह के व्यवहार सही नहीं हैं, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करने से आप सबकी नजरों में एग्रेसिव साबित होते हैं तो चुपचाप हर किसी की नाराजगी झेलने से आप सॉफ्ट टार्गेट बन जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि व्यवहार को संतुलित रखें क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आप अपना सही पक्ष नहीं रख सकतीं। इसलिए बेहतर है कि भीतर का आक्रोश थम जाने पर ही सामने वाले से बात करें। इससे आप जहां सही ढंग से अपना पक्ष रख सकेंगी, वहीं आपकी एनर्जी बेकार की बातों में वेस्ट नहीं होगी और काम पर भी उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा।

पर्सनल काम करें अवॉयड

ऑफिस के फोन से पर्सनल कॉल करना, ई-मेल पर चैट करना, प्रिंट पर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट लेना या फिर घरेलू कामों को निपटाना जैसे काम एक दिन बॉस के नोटिस में आ ही जाते हैं। ये सब आपकी कार्यक्षमता पर सवालिया निशान भी लगाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस प्रकार के पर्सनल कामों को अवॉयड किया जाए।

शालीन पहनावा

जब बात ऑफिस में प्रोफेशनल बिहेवियर की चल रही हो तो सही ड्रेसिंग भी उसी में आती है। यदि ऑफिस में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए ऑफिस में हमेशा ग्रेसफूल पोशाक ही पहनें, क्योंकि इसी से आपके सहयोगी आपके बारे में अपनी राय कायम करते हैं।

हॉबी भी बन सकती है कमाई का साधन

यदि आपकी भी कोई हॉबी है, तो

वह आपको अच्छा रिटर्न भी दे

सकती है। जरूरत है कि आप

अपनी हॉबी को अपना पैशन बना

लें, तभी तो वह आपको लाभ

देगी। पैशन को निवेश में बदलने

की शुरुआत करने पर उससे

संबंधित कुछ बातों को जानना

जरूरी है, तभी तो आप उसकी

सही कीमत पा सकती हैं और

अपनी कड़ी मेहनत से जुटाई

संग्रहणीय वस्तुओं को भी

सुरक्षित रख सकती हैं।



आपके पास स्टॉप का अच्छा-

खासा कलैक्शन हो जाए, तो

आप किसी खास देश की खास

स्टॉप पर भी फोकस कर

सकती हैं। इससे मिलने वाली

खुशी एक संकलनकर्ता का

प्रोत्साहन होती है, न कि उसके

संकलन की मार्केट वैल्यू उसके

लिए मायने रखती है।

अभिभावकों की भूमिका

अगर किसी बच्चे में कलैक्शन की

हॉबी है तो अभिभावक और शिक्षकों को उसे

प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिभावकों में अपने बच्चे

के टैलेंट को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।

प्रत्येक माता-पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चे

की कलैक्शन की आदत को पैशन बनाने में उसे

प्रोत्साहन दें। वे अपने बच्चे का परिचय ऐसी विभिन्न

सोसायटियों से करा सकते हैं, जहां पर पुराने और

बड़े संकलनकर्ता दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए

मीटिंग और सैमीनार आयोजित करते हैं। ये

सोसायटियां किसी संकलनकर्ता के संकलन की

जानकारी को लोगों से साझा करने और उनके

संकलन को विस्तृत बनाने के लिए जानकारीयां देने

में मददगार होती हैं।

विशिष्ट कलैक्टरों की जमात में शामिल होने के

लिए संकलनकर्ता को अपने संकलन के विषय की

गहन जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए अपने विषय

के अन्य संकलनकर्ताओं और उनके संकलन के स्तर

के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, सो इसके लिए

आप प्रदर्शनियों में जाएं तथा नैट पर सर्च करती रहें।

उपलब्धता भी रखती है मायने

आप जिस चीज का संकलन करने जा रहे हैं,

उसकी उपलब्धता का स्तर जानना बेहद महत्वपूर्ण है।

यह भी समझें कि विशिष्ट संकलनकर्ताओं के पास

संजोई गई चीजें आसानी से नहीं मिलती।

डीलर की पहचान जरूरी

स्टॉप, स्कल्चर और सिक्के बेचने वाले डीलरों

से कोई चीज खरीदने से पहले आप अच्छी तरह

जांच-पड़ताल कर लें कि वास्तव में वह वस्तु अपने

दाम के अनुरूप है या नहीं। एंटीक वस्तुएं खरीदते

समय प्रत्येक आइटम का गहनता से परीक्षण करना

होगा। इसकी भी जांच कर लें कि वह चीज अच्छी

स्थिति में हो और किसी अधिकृत संस्था द्वारा

प्रमाणित हो। एंटीक वस्तुएं खरीदते समय इस बात

का भी ध्यान रखें कि कहीं आप धोखाधड़ी का

शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी नई चीजों

को पुराना रूप देकर एंटीक बता दिया जाता है।

संग्रहणीय वस्तुओं की सुरक्षा

एक संकलनकर्ता को अपनी संग्रहणीय वस्तुओं

की गुणवत्ता के साथ किसी हाल में समझौता नहीं

करना चाहिए। उन्हें अपने संग्रहण की स्थिति की

समय-समय पर जांच करनी चाहिए। ऐसी चीजों को

इकट्ठा करने से बचना चाहिए, जो सही स्थिति में न

हों, हालांकि पुराने इस्तेमाल हो चुके स्टॉप इसके

अपवाद हो सकते हैं। संकलनकर्ता आम तौर पर

अपनी कलैक्शन को लेकर बेहद पोजेसिव होता है।

अपनी कलैक्शन को लोगों के हाथ में देकर दिखाने

की अपेक्षा दूर से दिखाना बेहतर तरीका है। सिक्कों के

संग्रहणकर्ताओं को अपने सिक्के साफ पानी से धोने

चाहिए। ऐसे रसायनों से बचना चाहिए जिनसे सिक्कों

की वास्तविक चमक कम हो जाती हो।

संकलनकर्ताओं को अपने संकलनको दुर्लभ,

अति दुर्लभ जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनका

कैटालॉग बनवा कर उनके विषय में लोगों को

जानकारी देनी चाहिए।

संकलन का बाजार

संकलनकर्ताओं को देखना चाहिए कि उनके

संकलन के लिए आसान खरीद और बिक्री का बाजार

हो। संकलित वस्तुओं को किसी मान्यता प्राप्त

अथॉरिटी से प्रमाणपत्र मिला होना चाहिए। संग्रहक

के पास अपने संकलन को बेहतर स्थिति में सुरक्षित

रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए।

पैशन को दें दिशा

अपने पैशन को यूं ही मत जाने दें। आपका यह

पैशन आपको किसी बड़े निवेश की ओर ले जा

सकता है। अगर आपको सिक्के इकट्ठे करने का शौक

है तो आप सिक्कों का एक बड़ा कलैक्शन कर इन्हें

बेच कर अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं अर्थात

आपकी हॉबी भी पूरी होगी और पैसा कमाने की

चाहत भी। पेंटिंग, स्कल्चर, स्टॉप तथा दुनिया के

तमाम देशों की करंसी इकट्ठा करने की आपकी हॉबी

आपको धनवान बना सकती है।

धनबाद में सख्ती: हाइवा दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 वाहनों पर 2.8 लाख का जुमाना

नवप्रदेश/धनबाद। निरसा-जमनाड़ा रोड पर हाइवा की टक्कर से दो छात्र घायल होने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने परिवहन नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कस दिया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने मेशन पावर लिमिटेड क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाकर 31 वाहनों पर कुल ₹2.8 लाख का जुमाना लगाया।

घटना के बाद हरकत में आया

प्रशासन.....

पिछले दिनों खुशरी और पांडुरा मोड़ के बीच तेज रफ्तार हाइवा ने दो बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

एमपीएल क्षेत्र में चला औचक अभियान.....



डीटीओ दिवाकर द्विवेदी के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने शुक्रवार को एमपीएल क्षेत्र में जांच

की। इस दौरान कोयला ढुलाई में लगे हाइवा और अन्य भारी वाहनों के कागजात, ओवरलोडिंग और

धनबाद समाहरणालय में लगा जनता दरबार, डीसी ने सुर्नी लोगों की फरियाद

नवप्रदेश/धनबाद। समाहरणालय स्थित जनता दरबार में शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने जिले भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर तय समय सीमा में निपटारा करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में कतरास, राजगंज, तोपचाची, गोमो,



गोविंदपुर, बाघमारा, बलियापुर, झरिया बरवाअड्डा और निरसा सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आवेदनकर्ताओं ने भूमि विवाद,

धनबाद में अपराध में 30% की गिरावट, लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

जून में 460 कांडों का निष्पादन, वारंट और यूडी मामलों में भी तेजी

नवप्रदेश/धनबाद। जिले में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा बैठक हुई। एसएसपी प्रभात कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सिटी एसपी ऋत्विंक श्रीवास्तव,ग्रामीण एसपी एस. एम. याकुब के साथ सभी डीएसपी, एसडीपीओ और थाना-ओपी प्रभारी मौजूद रहे।बैठक में जून महीने के क्राइम ग्राफ, अनुसंधान, वारंट और लंबित मामलों की बारीकी से



समीक्षा की गई।पुलिस के अनुसार जून में जिले में 409 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 460 मामलों का निपटारा कर दिया गया। यानी नए केस के साथ-साथ पुराने केसों पर भी फोकस रखा गया।लंबित कांडों की संख्या अब घटकर 1794 रह गई है। एसएसपी ने कहा कि टीम वर्क का नतीजा है और

गति सीमा की बारीकी से जांच की गई। जांच में नियम तोड़ने वाले 31 वाहनों को पकड़ा गया।

नियम तोड़ने पर कसी नकेल.....

परिवहन विभाग ने ओवरलोड, गति सीमा उल्लंघन और दस्तावेज नहीं पाए जाने पर इन 31 वाहनों पर कुल ₹2.8 लाख का जुमाना वसूला। अधिकारियों ने मौके पर ही चालकों और वाहन मालिकों को यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी।

डीटीओ की चेतावनी.....

जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी. द्विवेदी ने कहा कि ₹आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी उद्योगों और ट्रंसपोर्टरों की थोपे चालकों को निबंत्रित गति से वाहन चलवाना होगा। आगे नियमों की अन्देखी मिली तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों में हड़स्रम मच गया है।

प्रमाण पत्र के आधार पर आगनवाड़ी सेविका पद पर बने रहने, मंदिर निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने, धोखाधड़ी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष रखा। सभी आवेदनों का सज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है।

प्रमाण पत्र के आधार पर आगनवाड़ी सेविका पद पर बने रहने, मंदिर निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने, धोखाधड़ी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष रखा। सभी आवेदनों का सज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है।

कि जिले में अपराध घटे हैं। पिछले साल हर महीने औसतन 600 केस दर्ज होते थे, जो अब घटकर करीब 400 रह गए हैं। यानी लगभग 30% की कमी आई है।सड़क हादसों में भी मई की तुलना में जून में 33% की गिरावट दर्ज की गई। एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था और जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया।

अनुसंधान के मोर्चे पर भी पुलिस को सफलता मिली।जून में 509 पुराने मामलों में चार्जशीट और अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में सौंप गए।

ऑनलाइन मिली 46 शिकायतों में से 30 का निपटारा भी हो चुका है।

डिजिटल युग के लिए तैयार हो रहे झारखंड के आदिवासी छात्र



को पायथन प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल और अन्य डिजिटल उपकरणों का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया गया।कक्षा में लाइव डेमो, केस आधारित अभ्यास और इंटरैक्टिव सत्र कराए गए। कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रों ने स्वयं प्रोजेक्ट बनाकर अपनी सीख को चलेा।

आईआईटी- आईएसएम में जुलाई 2024 से संचालित इस एक वर्षीय कार्यक्रम के तहत झारखंड के 7 ईएमआरएस स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्रों को उद्योग की जरूरत के अनुसार डिजिटल कौशल से लेस

धनबाद व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश

डीएसपी ने किया औचक निरीक्षण



गतिविधि की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम और वरीय अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। न्यायालय परिसर के वाहन पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया गया। डीएसपी ने निर्देश दिया कि वाहनों की पार्किंग सुव्यवस्थित तरीके से हो। बिना जांच के किसी भी संदिग्ध वाहन को अंदर प्रवेश न दिया जाए। पार्किंग क्षेत्र में नियमित रूप से पुलिस गश्त कराई जाए ताकि किसी अश्रिय घटना से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान हाजत और जेल गेट पर भी सुरक्षा व्यवस्था परीक्षी दी। डीएसपी ने बंदियों की आवाजाही,एस्कॉर्ट पार्टी की

सतर्कता और प्रवेश-निकास व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मीयों को आने-जाने वाले लोगों की कड़ी जांच करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा।

इयूटी पर मौजूद सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को डीएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि न्यायालय परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी जवान सतर्क रहें, सदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं पर विशेष नजर रखें, नियमित जांच अभियान चलाए और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।डीएसपी ने कहा कि न्यायिक पदाधिकारियों,अधिवक्ताओं कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जा रहें हैं।

वर्णवाल सेवा समिति की संरक्षक गिरिजा देवी की निधना

नवप्रदेश/बाघमारा। वर्णवाल सेवा समिति बाघमारा के संरक्षक और मुराइडीह कॉलोनी निवासी व्यवसायी रामबिलास वर्णवाल की पत्नी गिरिजा देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 70 वर्ष की थीं। गिरिजा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है। वे भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके निधन पर समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार, प्रहलाद वर्णवाल, महेंद्र विक्रम, उपेन्द्र वर्णवाल, मनोज मोदी, किशोर वर्णवाल, संजय वर्णवाल, अशोक वर्णवाल, केदार वर्णवाल, सुभाष वर्णवाल, सुनील वर्णवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

परिवार कल्याण मेले का आयोजन,जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा -पुरुषों को भी शिक्षा

नवप्रदेश/धनबाद। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शुक्रवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित एपटीसी भवन में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिवार कल्याण मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।श्रीमती सिंह ने कहा कि मेले का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है। इसमें सहभागिता की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और कम उम्र में विवाह बाधा बनते हैं, लेकिन अब सोच बदल रही है। रछोटा परिवार सुखी परिवारह के तहत दो बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर जरूरी है।सिविल सर्जन डॉ. अलोक विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 -26 में जिले में 82 पुरुषों और 4825 महिलाओं की नसबंदी हुई। यह स्वास्थ्य विभाग, आशा और सहयोगी संस्थाओं के टीमवर्क का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुषों को भी आगे आना होगा और पुरुष नसबंदी को लेकर फैली प्रतियौ को दूर करना होगा।डॉ. विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि 10 अगस्त तक सभी प्रखंडों और पंचायतों में परिवार कल्याण मेले लगाए जाएंगे। इनमें दक्षिंतियों को परिवार नियोजन के सुरक्षित उपायों की जानकारी दी जाएगी।कार्यक्रम में नुकुंड नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने के साथ परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एमओआईसी और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। परिवार नियोजन संबंधी पोस्टर का भी विमोचन हुआ।मौके पर जिला आरसीओ पदाधिकारी डॉ. रोहित गौतम,टोपीएम प्रतिमा कुमारी,डीपीसी रेखा सिंह,श्रीबीडी सलाहाकर रमेश कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।

डीसी का निर्देश: विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर पूरा करें सभी योजनाएं

नवप्रदेश/धनबाद। जिले के विकास कार्यों को गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला योजना कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला योजना समिति के अध्यक्ष आदित्य रंजन ने की।बैठक में अनाबद्ध निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत

चर्चा हुई। मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी प्रस्तावों की गहन समीक्षा के बाद कई प्रस्तावों को समिति ने स्वीकृति प्रदान की। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन पाददूर्ण और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में शिथिलता और लापरवाही किसी



भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय- सीमा के भीतर पूरा

करना होगा। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिले के सभी

पंचायत भवनों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि भवनों के बेहतर उपयोग और उनसे आय बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।इसके साथ ही उन्होंने ऐसे सरकारी भवनों को चिन्हित कर उपयोगी योग्य बनाने को कहा जो वर्तमान में अनुपयोगी पड़े हैं। इन भवनों को स्वयं सहायता समूह की दीर्घियों को आजीविका

गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में संचालित सभी दाल-भात केंद्रों के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण कर उन्हें मॉडल दाल-भात केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

एक नजर

6 विधानसभा क्षेत्रों में 13 लाख 04 हजार 882 मतदाताओं को ईएफ वितरित

नवप्रदेश/धनबाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर 2026) के लिए धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 13 लाख 04 हजार 882 मतदाताओं को ईएफ वितरित किया जा चुका है। जबकि 2 लाख 87 हजार 639 ईएफ का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। विधानसभा वार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सिंदरी विधानसभा में 269061,निरसा में 242825, टुंडी में 236973,धनबाद में 223712,बाघमारा में 179574, तथा झरिया विधानसभा में 152741 सहित 13,04,882 ईएफ का वितरण किया गया है। जबकि निरसा में 78839,सिंदरी में 68199, टुंडी में 49644,बाघमारा में 37850, धनबाद में 28088 तथा झरिया विधानसभा में 25019 सहित 2,87,639 ईएफ का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने-अपने विधानसभा में मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

बाघमारा में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल, बेहराकुदर में पीएम -अभिम उप-केंद्र का शिलान्यास

नवप्रदेश/बाघमारा। क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीपुम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन’ के तहत बेहराकुदर में नए स्वास्थ्य उप-केंद्र का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मुख् अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ गिरिडीह सांसद के प्रतिनिधि सुभाष रवानी भी मौजूद रहे।दीप प्रज्वलन और नारियल फोड़कर विधायक ने केंद्र की आधारशिला रखी।पीएम- अभिम योजना के तहत बनने वाले इस उप-केंद्र से बेहराकुदर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। अब प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को दूरदराज के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उप-केंद्र के शुरू होने से हजारों लोगों को उनके घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।इससे इलाज में लगने वाले समय और खर्च दोनों में कमी आएगी।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए उप-केंद्र में प्राथमिक उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और आवश्यक दवाओं की सुविधा उपलब्ध रहेगी।स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे क्षेत्र की समग्र चिकित्सा व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।

धनबाद में कांग्रेस की समीक्षा बैठक, बृथ स्तर पर अभियान तेज करने के निर्देश

नवप्रदेश/धनबाद। धनबाद संसदीय क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को लुबी सर्कुलर रोड स्थित स्वामी सहजानंद सेवा ट्रस्ट भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने की।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एआईसीसी सचिव एवं झारखंड प्रभारी भूपेंद्र मरावी शामिल हुए।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण ही लोकतंत्र की नींव है।प्रत्येक कार्यकर्ता को बृथ तक पहुंचकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और लोगों को मतदान से जोड़ने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अनुशासन पर भी जोर देते हुए कहा कि पार्टी से जुड़े मामलों को सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया जाएगा।शहरी जिला प्रभारी शकील अख्तर और ग्रामीण प्रभारी रakesh किरण महतो ने कहा कि अभियान को गांव-गांव और वार्ड- वार्ड तक लाना होगा। बांकागो जिलाध्यक्ष जवाहर महता ने दोनों जिलों में समेकित कार्य करने की अपील की।जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि संगठन शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा। बैठक में प्रखंडवार रिपोर्ट ली गई और आगे की रणनीति तय की गई। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण तिवारी ने किया।

धनबाद के गायक अभिषेक को मेयर और विधायक ने किया सम्मानित राष्ट्रीय मंच पर जिले का नाम रोशन करने पर जताया आभार



नवप्रदेश/धनबाद। इंडियन आइडल से पहचान बनाने वाले धनबाद के युवा गायक अभिषेक शुक्रवार को सिंह मेशन पहुंचे। यहां उन्होंने धनबाद के मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह से मुलाकात की।इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने अभिषेक को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मेयर और विधायक ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।की मेयर संजीव सिंह ने कहा कि अभिषेक ने अपनी मधुर आवाज से न केवल धनबाद बल्कि पूरे कोयलांचल को गौरवान्वित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभिषेक अपनी मेहनत से संगीत की दुनिया में और ऊंचा नाम करेंगे।विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि युवा कलाकार किसी भी क्षेत्र की असली पूंजी होते हैं।अभिषेक ने अपनी कला से झारखंड का नाम बढ़ाया है। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।सम्मान से अभिभूत अभिषेक ने दोनों का धन्यवाद किया और कहा कि उनका प्रोत्साहन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

नवप्रदेश/बाघमारा। वर्णवाल सेवा समिति बाघमारा के संरक्षक और मुराइडीह कॉलोनी निवासी व्यवसायी रामबिलास वर्णवाल की पत्नी गिरिजा देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 70 वर्ष की थीं। गिरिजा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है। वे भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके निधन पर समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार, प्रहलाद वर्णवाल, महेंद्र विक्रम, उपेन्द्र वर्णवाल, मनोज मोदी, किशोर वर्णवाल, संजय वर्णवाल, अशोक वर्णवाल, केदार वर्णवाल, सुभाष वर्णवाल, सुनील वर्णवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

परिवार कल्याण मेले का आयोजन,जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा -पुरुषों को भी शिक्षा

नवप्रदेश/धनबाद। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शुक्रवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित एपटीसी भवन में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिवार कल्याण मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।श्रीमती सिंह ने कहा कि मेले का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है। इसमें सहभागिता की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और कम उम्र में विवाह बाधा बनते हैं, लेकिन अब सोच बदल रही है। रछोटा परिवार सुखी परिवारह के तहत दो बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर जरूरी है।सिविल सर्जन डॉ. अलोक विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 -26 में जिले में 82 पुरुषों और 4825 महिलाओं की नसबंदी हुई। यह स्वास्थ्य विभाग, आशा और सहयोगी संस्थाओं के टीमवर्क का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुषों को भी आगे आना होगा और पुरुष नसबंदी को लेकर फैली प्रतियौ को दूर करना होगा।डॉ. विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि 10 अगस्त तक सभी प्रखंडों और पंचायतों में परिवार कल्याण मेले लगाए जाएंगे। इनमें दक्षिंतियों को परिवार नियोजन के सुरक्षित उपायों की जानकारी दी जाएगी।कार्यक्रम में नुकुंड नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने के साथ परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एमओआईसी और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। परिवार नियोजन संबंधी पोस्टर का भी विमोचन हुआ।मौके पर जिला आरसीओ पदाधिकारी डॉ. रोहित गौतम,टोपीएम प्रतिमा कुमारी,डीपीसी रेखा सिंह,श्रीबीडी सलाहाकर रमेश कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलीं आरएलएम जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद

महिषी की जर्जर सड़कों के निर्माण की उठाई मांग

● वीरगांव सहित दर्जनों पंचायतों की सड़क मरम्मत व निर्माण को लेकर सौपा आवेदन, जनहित में शीघ्र कार्रवाई की अपील

नवप्रदेश/सहरसा। राजधानी स्थित लोक सेवक भवन (मुख्यमंत्री आवास) में शुक्रवार को आयोजित एनडीए के जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) की सहरसा जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर महिषी विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।



इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत

वीरगांव सहित दर्जनों पंचायतों

की सड़क निर्माण एवं मरम्मत की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत आवेदन पत्र भी सौंपा। अर्चना आनंद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्षों से सड़कें जर्जर होने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जनहित को देखते हुए संबंधित सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया।

बैठक के बाद अर्चना आनंद ने कहा कि यह दिन महिषी विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर वीरगांव पंचायत की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के विश्वास

तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष यह महत्वपूर्ण जनसमस्या रखने का अवसर मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करेंगे। अर्चना आनंद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा एवं क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाती रहेंगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी।

कार्य बार संभाली नया वीडियो गिरधारी लाल

नवप्रदेश/नौतवा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में विकास कर््यों का निष्पादन किया जाएगा। समाज के अंतिम जन तक विकास कर््यों की रैशनी पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बुधवार को प्रखंड कार्यालय में नये वीडिओ गिरथारी लाल ने कार्यभार संभालने के उपरांत कहीं। तत्कालीन वीडिओ शैलेन्द्र कुमार सिंह ने नये वीडिओ को अपने कार्य भार सौंप दिया। इस दौरान मौजूद प्रखंड प्रमुख कृष्ण देव चौधरी, उप प्रमुख अप्सर हुसैन ने नये वीडिओ गिरथारी लाल का स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने नये वीडिओ गिरथारी लाल से विकास की गति तेज करने की अपेक्षा किया। प्रमुख ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कर््यों को आगे बढ़ाते हुए गांव और पंचायत को ससक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

बीईओ ने किया मौसमी फल वितरण का शुभारंभ

नवप्रदेश/गया/टिकारी। गया जिले के टिकारी स्थित टाउन मध्य विद्यालय में शुक्रवार को मौसमी फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) डॉ. अभय कुमार रमण ने बच्चों के बीच पके आम वितरित कर किया।इस अवसर पर डॉ. रमण ने अपने हाथों से छात्र-छात्राओं को आम देकर उन्हें मौसमी फलों के सेवन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्क आहार उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तिथि भोजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक रिन्दु कुमार सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।बीईओ डॉ. अभय कुमार रमण ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि आम के मौसम में बच्चों को नियमित रूप से मौसमी फल के रूप में आम उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि तिथि भोजन और मौसमी फल वितरण जैसी पहल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

श्री त्रिदंडी स्वामी डिग्री महाविद्यालय में ऑडिटोरियम के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे

नवप्रदेश/पटना। परमानपुर के परमानंद नगर स्थित निमाणांधीन श्री त्रिदंडी स्वामी डिग्री महाविद्यालय में प्रस्तावित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण परियोजना को लेकर शुक्रवार को टोपोग्राफिकल सर्वे किया गया। निर्माण कार्य से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ईंडियन रेलवे फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा महाविद्यालय में प्रस्तावित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सर्वे का कार्य कंपनी के निदेशक मुकेश नारायण सिन्हा के नेतृत्व में तकनीकी टीम द्वारा संपन्न किया गया। सर्वे के दौरान निर्माण स्थल की भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक स्थिति, भूमि के स्तर, माप, ढाल तथा अन्य आवश्यक तकनीकी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप ऑडिटोरियम का विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए निर्माण प्रस्तावित अत्याधुनिक



ऑडिटोरियम के निर्माण से महाविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सेमिनार, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे भविष्य में विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व विकास को नई दिशा एवं गति मिलेगी तथा क्षेत्र में उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण एवं कॉलेज के सपने को साकार करने में अहम योगदान देने वाले छोटेताल वि्तारी ने बताया कि पूंय श्री जीयर स्वामी जी की कृपा से गांव में डिग्री कॉलेज का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के निर्माण एवं आधुनिक ऑडिटोरियम की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा।

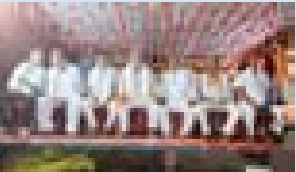
बिक्रमगंज में एसडीएम के जनता दरबार में 65 मामले का किया गया निष्पादन

नवप्रदेश/बिक्रमगंज। सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी रोहतास दिपक कुमार मिश्र के आदेश पर शुक्रवार को एसडीएम बिक्रमगंज प्रभात कुमार ने अपने कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किये। एसडीएम बिक्रमगंज द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित रसबका सम्मान-जीवन आसानर के तहत आयोजित जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र से आम नागरिक उपस्थित हुए थे। इस दौरान अनुमंडल क्षेत्र से कुल 65 आवेदन पड़े। जिसमें भूमि विवाद से संबंधित 30, राशन कार्ड से संबंधित 18 एवं अन्य 17मामलें लेकर परिवादी उपस्थित हुए। सभी ने अपनी-अपनी समस्याएं रखी तथा एसडीएम को आवेदन सौंपा। एसडीएम ने सभी आवेदन पत्रों का अवलोकन करने के उपरांत शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित कार्यालयों व पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य है कि आम लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उनकी समस्याओं का समाधान ही हमारी प्राथमिकता है। जनता दरबार में भूमि सुधार उपसमार्हां संतोष कुमार, सभी प्रखंड के बीडीओ, अंचल के सीओ और कई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।



क्रिकेट मैच का प्रखंड प्रमुख रामचंद्र यादव ने किया उद्घाटन

नवप्रदेश/चर पोखरी भोजपुर। प्रखंड के खेल मैदान धनौती में नाइट क्रिकेट मैच का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख चरपोखरी रामचंद्र यादव फीता काटकर किया। इस अवसर पर आयोजन समिति धनौती के सदस्यों को आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख ने कहा कि क्रिकेट मैच का आयोजन कर अच्छा कार्य किए हैं। ऐसा कार्यक्रम पंचायत में होने से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी का चयन होता है। जो पंचायत से प्रखंड स्तर पर खेल कर जिला स्तर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं ।ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। बच्चों के उपलब्धि के लिए सरकार द्वारा खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है ।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं उन्होंने खिलाड़ियों से मैत्रीपूर्ण संघर्ष बनाकर खेलने का कार्य करने की अपील की।आयोजित कार्यक्रम के बाद अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया ।प्रखंड प्रमुख ने गैंग मार कर क्रिकेट खेल का शुरुआत किया ।आयोजित नाइट क्रिकेट खेल में प्रखंड के विभिन्न गांव से दर्जनों क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यक्रम में क्रिकेट क्लब धनौती के सदस्यों द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।



ग्राम स्तरीय योजना मूल्यांकन अभिसरण समिति व सर्वेक्षण दल का प्रशिक्षण आयोजित

नवप्रदेश/पीरों। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत पीरों प्रखंड के महुअरी,बवउड व सुग्रीवाल में गठित ग्राम स्तरीय योजना मूल्यांकन अभिसरण समिति व सर्वेक्षण दल के सदस्यों का प्रशिक्षण प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद भवन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी सदस्यों को उक्त योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि यह योजना इस साल से चयनित गांवों में लागू होगी है। इसमे संबंधित गांव में आवश्यकता आधारित सर्वे के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा तथा तैयार विकास योजना का अनुमोदन ग्राम सभा से करने के पश्चात जिला स्तरीय योजना मूल्यांकन एवं अभिसरण से अनुमोदन कराकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा चयनित गांव के विकास के लिए प्रति गांव 21 लाख रुपये की दर से धनराशि दी जाएगी। जिसमे 20 लाख रुपये की राशि चयनित गांव में अन्तर पूर्ति घटक/गैप फिलिंग/कंजरवेंस के कार्य में खर्च की जाएगी। शेष एक लाख रुपये प्रशासनिक व मान्य खर्चों अर्थात तकनीकी सहायता,प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण आदि कार्यों में खर्च होगी।

ठगों ने 79 हजार रूपया का लगाया चूना

नवप्रदेश/शाहपुर। करनामेपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गाँव के एक व्यक्ति के साथ ठगी कर 79 हजार रूपया ठगों ने चंपत कर लिया। सोनबरसा गाँव के रोहित कुमार साह एसबीआई करनामेपुर शाखा से 79 हजार निकाल कर अपने घर जा रहे थे। रास्ते मे रामदतही-महुआर मोड़ के पास दो लोग उसके पास आये और ज़्यादा रकम देने की बात कह कर अपने नोटों की गि़ठी रोहित कुमार साह को थमा दिया और बदले में रोहित कुमार साह से उसका 79 हजार रुपया ले कर फसार हो गये। ठगों ने रोहित कुमार साह को जाली रूपया थमा दिया और उसका असली रुपया लेकर चंपत हो गये। रोहित कुमार साह को ठगों द्वारा रूमाल सुंघाकर उसका रुपया ले लेने की बात भी चर्चा में है।

नहर पुल में एक किशोर डूबा, शव की तलाश में जुटे ग्रामीण, प्रशासन से मांगे सहयोग

नवप्रदेश/बिक्रमगंज। थाना क्षेत्र के जोन्ही गाँव के समीप शुक्रवार को नहर में नहाने के दौरान एक किशोर डूब गया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण नहर पुल पर जमा हो गए। किशोर के शव की तलाश जारी है। बताया गया कि जोन्ही निवासी मो. सैयद खां उर्फ जोधा खां का 14 वर्षीय पुत्र सिकंदर खां अपने कुछ दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। नहाते समय पैर फिसलने के कारण वह नहर की तेज धार में बह गया। उसके दोस्तों ने गांव में जाकर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण नहर की ओर दौड़े और कुछ युवक नहर के तेज बहाव में किशोर के शव की तलाश में जुट गए। हालांकि, अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीण प्रशासन से नहर का पानी बंद कराने और गोताखोरों की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग को नहर बंद करने का निर्देश दिया गया है। गोताखोरों की व्यवस्था भी की जा रही है।



पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल संसदीय समिति की बैठक का आयोजन

नवापदेश/हाजीपुर । 10.07.2026 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल की 'मंडल संसदीय समिति' की बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, डीडीयू के सभागार में किया गया। इस बैठक में पं.दीन दयाल उपाध्याय मंडल क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदगण ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता पलामू के माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम द्वारा की गयी। बैठक में माननीय सांसदगण द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे एवं रेल के सर्वांगीण विकास हेतु अपने-अपने सुझावों को रखा गया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह, पं.दीन दयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री उदय सिंह मीना सहित मुख्यालय एवं मंडल के अधिकारीगण उपस्थित थे।



आज की इस बैठक में पलामू के माननीय सांसद विष्णु दयाल राम, चंदौली के माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह, काराकाट के माननीय सांसद राजा राम सिंह, आरा के माननीय सांसद श्री सुदामा प्रसाद, सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार, औरंगाबाद के माननीय सांसद श्री अभय कुमार सिन्हा तथा राज्य सभा की माननीय सांसद श्रीमती साधना सिंह उपस्थित थे। इनके अलावा माननीय केन्द्रीय मंत्री सुक्ष्म, लघु और माध्यम

उद्यम, भारत सरकार सह गया के माननीय सांसद श्री जीवन राम मांझी के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार पाण्डेय, बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह के प्रतिनिधि अजीत कुमार तथा राज्य सभा की माननीय सांसद दर्शना सिंह के प्रतिनिधि श्री विवेकानंद केसरी उपस्थित थे। बैठक में माननीय सांसदगण ने रेल विकास व यात्री सुविधाओं में और वृद्धि एवं उसे सुदृढ़ करने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिये। माननीय सांसदगण द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर बल दिया गया। साथ ही बैठक में भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक के प्रारंभ में महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने माननीय सांसदगण एवं माननीय सांसद के प्रतिनिधिगण का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक रेलवे एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य संवाद का एक सशक्त माध्यम है और आपके सुझाव हमें सेवा की गुणवत्ता में और सुधार लाने हेतु प्रेरित करते हैं। महाप्रबन्धक ने अपने स्वागत संबोधन में पं.दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा यात्री सुविधा, आधारभूत संरचनाओं के विकास आदि के क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं नई परियोजनाओं से माननीय सांसदगण को अवगत कराया।



त्व्रित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पैनल की वैधता एक वर्ष निर्धारित की गई है। महापौर श्रीमती सिका्रिया ने बताया कि इसी निर्देश के आलोक में नगर निगम, बेतिया ने निविदा जारी करते हुए बताया है कि निविदा दस्तावेजों का डाउनलोड 13 जुलाई 2026 की अपराह्न तीन बजे से शुरू होगा। प्री-बिड बैठक 15 जुलाई को अपराह्न चार बजे नगर आयुक्त कार्यालय में आयोजित होगी। ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई को शाम चार बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि तकनीकी दावेदारी पर 22 जुलाई को निर्णय लिया जाएगा। महापौर श्रीमती सिका्रिया ने बताया कि जारी निविदा में उल्लेख है कि पांच हजार रुपये का गैर-वापसी योग्य प्रोसेसिंग शुल्क तथा एक लाख रुपये की वापसी योग्य ईएमडी निर्धारित की गई है।

एक नजर

थानाध्यक्ष चंदन कुमार भगत ने छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

नवप्रदेश/सूर्यपुर। प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवोबहार में शुक्रवार को नवम एवं दशम वर्ग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को थानाध्यक्ष चंदन कुमार भगत ने साईबर फ्रेंड, सड़क सुरक्षा तथा नशामुक्ति के साथ ही अन्य बातों की जानकारी दे सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि भारत में साइबर अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले गैर कानूनी कार्य को रोकने और नियंत्रित करने के लिए मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2008 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे. वहीं सड़क सुरक्षा पर छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा अधिनियम जीवन बचाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है. हमेशा निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलाएं. दो पहिया वाहन पर हेलमेट, सड़क सुरक्षा नियम डिजिटल और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वहीं नशा मुक्ति पर सभी को टिप्स देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. यह अभियान देश के युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। मौके पर एसआई अनामिका सुधा के साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।



हाईकोर्ट के आदेश पर वर्षों पुराने भूमि विवाद का हुआ पटाक्षेप

नवप्रदेश/नरकटियागंज (प. चंपारण)। साठी थाना क्षेत्र के भेड़िहरवा गांव में वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद का हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पटाक्षेप हो गया। अंचल प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक पक्ष को करीब छह कट्ठा भूमि का दखल-कब्जा दिलाया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।जानकारी के अनुसार, यह भूमि विवाद संजय कुमार पांडेय उर्फ अभिनव कुमार पांडेय और राजदेव यादव के बीच लंबे समय से चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नरकटियागंज प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में अंचल प्रशासन एवं साठी थाना पुलिस की टीम भेड़िहरवा गांव पहुंची।प्रशासन की निगरानी में भूमि की विधिवत मापी कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद संजय कुमार पांडेय उर्फ अभिनव कुमार पांडेय को संबंधित भूमि का दखल-कब्जा दिलाया गया। राजस्व पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यदि किसी भी पक्ष को इस कार्रवाई पर आपत्ति है, तो वह सक्षम न्यायालय में अपनी बात रख सकता है। न्यायालय से प्राप्त होने वाले किसी भी नए आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।



रोहतास के नए डीएम दीपक कुमार मिश्रा का SAFA ने किया अभिनंदन

नवप्रदेश/सासाराम। रोहतास के नवपदस्थायित जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा के पदभार ग्रहण करने पर सोसाइटी अग्रेस्ट फूड एक्ट्लरेशन (SAFA) ने उनका अभिनंदन करते हुए सफ़न, पादरशी एवं जनहितपी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। संस्था के अध्यक्ष पंकज कुमार ने जारी संदेश में कहा कि उन्हे विश्वास है कि श्री मिश्रा के कुशल, दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में रोहतास में सुशासन, जनकल्याण, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा समग्र विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पारदर्शी कार्यशैली और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जाने वाले प्रयास जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंकज कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाना तथा लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन की सक्रिय पहल से खाद्य जांच अभियान, जनजागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्य को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि रसद्वारा खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है तथा भविष्य में भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समाजहित के कार्यों में हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।



बिहार में अपराधियों का तांडव: दरभंगा में युवक को सरेआम गोली

नवप्रदेश/पटना। बिहार में अपराधियों के हाँसेले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद अब दरभंगा और सीवान में हुई दो बड़ी वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिर्मेटी चौक पर गुजरावर देर रात बाइक सवार संजीव कुमार सिंह को अज्ञात अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी। बताया जाता है कि संजीव एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।वहीं, सीवान जिले के लहेरगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव में एक युवक ने चार लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों में एक युवती भी शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।दोनों घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है।

पटना में एनडीए की अहम बैठक, जिला से ब्लॉक स्तर तक तालमेल मजबूत करने पर जोर

नवप्रदेश/पटना। मुख्यमंत्री सस्मट चौधरी के पटना स्थित एक अणे मार्ग आवास पर शुक्रवार को एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो के जिलाध्यक्षों व वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक से पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर जिला और ब्लॉक स्तर तक मजबूत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर तालमेल बढ़ाकर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है।संजय झा ने कहा कि पिछले चुनाव के बाद भिले फीडबैक की भी समीक्षा की जाएगी। जिलाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति, विकास योजनाओं, जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय समस्याओं की जानकारी देंगे। इन सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति और योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंच सके।



बाइक सवार को धक्का देकर भरा बैग झपटकर 2.55लख लूटकर अपराधी हुए फरार

नवप्रदेश/बेतिया। चनपटिया थाना क्षेत्र के खेरवाटोला भंसाही के बीच पोखरा के नजदीक रात बाइक सवार स्वास्थ्यकर्मी से 2.55 से भरा बैग झपट कर दोअज्ञात बदमाश फरार हो गए।घटना के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में जा गिरी, जिससे स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए,मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ित की पहचान चुाही निवासी.27 वर्षीय बासु कुमार.सिकंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एकर-रे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार देर शाम वहअपने घर से बाइक पर सवार होकर बैग में 2.55 लख रूपए लेकर बगहा निवासी.एरिया मैनेजर सोहैल खान को देने शनिचरी चौक जा रहे थे, इसी दौरान खैरवाटोला भंसाई पोखरा के पास झड़ियां में छुपे दो बदमाश अचानक निकले,साथ ही रूपए से भरा बैग झपटकर फरार हो गए।

संक्षिप्त खबरें

बांकीपुर से अभिषेक कुमार की जगह नीरज कुमार सिन्हा होंगे भाजपा उम्मीदवार

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से अपने घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार के स्थान पर नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। यह निर्णय अभिषेक कुमार के पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद लिया गया।

अभिषेक कुमार ने पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को संबोधित पत्र सौंपते हुए पारिवारिक कारणों का हवाला दिया और चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई। गौरतलब है कि अभिषेक कुमार ने गुरुवार को ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के बाद आयोजित सभा में बिहार के मुख्यमंत्री सप्रिट चौधरी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी प्रमुख घटक दलों के नेता उपस्थित थे।

अंतरराज्यीय नवजात तस्करी गिरोह का पदांश, 10 और आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली की मध्य जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय नवजात एवं बच्चों की तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में 10 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें जैविक माता-पिता, दलाल, खरीदार, बिचौलिया और एक अस्पताल संचालक भी शामिल हैं। पुलिस ने दिल्ली, उप्र और उत्तराखंड के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर चार और बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इस मामले में अब तक कुल नौ बच्चों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। जांच के दौरान पुलिस ने कई लाख रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा किया है। बैंक खातों के जरिए हुए भुगतान की भी जानकारी सामने आई है और अब पुलिस पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है।

मणिपुर में छह नागा ग्रामीणों की हत्या के आरोप में दंपती गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने एक संयुक्त अभियान में 13 मई को लेइलोन वाइफेई गांव में छह नागा ग्रामीणों की हत्या में कथित तौर पर शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस के अनुसार, यह अभियान शुक्रवार की सुबह खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों ने लेइलोन वाइफेई गांव में एक चिह्नित अभियान चलाया, जिसके बाद दो सदियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रदीप और उसकी पत्नी अथिंगबी के तौर पर हुई है। ये दोनों लेइलोन वाइफेई गांव के निवासी बताये गये हैं। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई और अभी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिएएं चल रही हैं। यह मामला 13 मई को लेइलोन वाइफेई गांव में छह नागा लोगों की हत्या से जुड़ा है। चूंकि जांच अभी चल रही है, इसलिए अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा नहीं की है।

चीन के जिनजियांग में जूता फैक्टरी में आग लगने से 28 की मौत



बीजिंग। चीन के दक्षिण-पूर्वी फुजियान प्रांत के जिनजियांग शहर स्थित एक जुते की फैक्टरी में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 211 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के वक्त फैक्टरी परिसर में कुल 239 कर्मचारी मौजूद थे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आग स्थानीय समाना्यार गुरुवार दोपहर जूता निमातां कंपनी हुइटेंग की बहुमंजिला फैक्टरी में लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कई कर्मचारी इमारत की छत पर फंस गए। सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो में इमारत से उठती ऊंची लपटें और आसमान में फैलता घना काला धुआं देखा गया। घटना के समय फैक्टरी में 239 कर्मचारी मौजूद थे। बचाव दल ने 213 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन इसमें से दो कर्मचारियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और लापता 26 अन्य कर्मचारियों के शव बाद में बरामद हुए। प्रचिन्युआ और अन्य मीडिया रिपोर्ट के निचले तल से शुरू हुई। जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील सामग्री और चिपकाने वाले रसायनों के कारण आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई। वही, सीढ़ियों पर बड़ी मात्रा में रखा सामान बचाव और अग्निशमन कार्य में बाधा बना। अग्निशमन विभाग ने बताया कि कई घंटों की मशकत के बाद आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, हालांकि देर शाम तक घटनास्थल से धुआं उठता रहा और दमकल की गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव करती रहीं। घटना के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज एवं बचाव अभियान में हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के महीनों में कार्यस्थलों पर हुई कई गंभीर दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए देशभर में औद्योगिक सुरक्षा उपायों को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी संबंधित विभागों को कार्यस्थलों पर सुरक्षा जोखिमों की व्यापक जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शिन्हुआ के अनुसार फैक्टरी के जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कंपनी के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने घटनास्थल पर एक विशेष टीम भेजी है, जबकि फुजियान प्रांतीय प्रशासन घायलों के इलाज और राहत कार्यों की निगरानी कर रहा है। गौरतलब है कि जिनजियांग शहर चीन के सबसे बड़े जूता और परिधान निर्माण केंद्रों में शामिल है और इसे अक्सर देश की जूता राजधानी कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां की हजारों कंपनियों ने वर्ष 2024 में 1.2 अरब से अधिक जूता जूतों का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है।

रामभक्तों पर गोली चलाने के लिए समाजवादी पार्टी माफी मांगे : योगी आदित्यनाथ

बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बस्ती के हरैया और कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों में 504.34 करोड़ रुपये की 77 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार देते हुए कहा कि रामभक्तों पर गोली चलाने के लिए समाजवादी पार्टी माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के बाद हरैया पहुंचे। यहां विकास की कुल 504.34 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें हरैया विधानसभा में 85.54 करोड़ रुपये की 22 नई परियोजनाओं का

शिलान्यास और 275.76 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जबकि कप्तानगंज विधानसभा में 62.08 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और 80.96 करोड़ रुपये की पूर्ण हो चुकी 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। विकास कार्यों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन विकास कार्यों से हरैया और कप्तानगंज के विकास की गति तेज होगी, क्योंकि वर्ष 2017 से पहले इन दोनों क्षेत्रों को विकास से उपेक्षित रखा गया और किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने

अपनी सरकार की हर क्षेत्र की उपलब्धियां गिनायीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विकास विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दोनों राम विरोधी और संविधान विरोधी हैं। इन दोनों की जब सरकारें थीं तो गरीबों को लूटा जाता था और विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। उन्होंने कहा कि ये आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियों ने हमेशा राम मंदिर और सनातन धर्म के विरोध में काम किया है। रामभक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी को अब माफी मांगनी चाहिए। सपा को कांवड़ यात्रा और पंचकोशी परिक्रमा रोकने के लिए माफी

मांगनी चाहिए,लेकिन अब राम राज्य में न तो कांवड़ यात्रा रुकती है और न ही मंदिर का पैसा कब्रिस्तान के निर्माण पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरैया और कप्तानगंज में विकास कार्यों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी भारी धनराशि स्वीकृत की है और

सरकार सनातन धर्म पर कि री पकार का अंश नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि बहु बेदियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। व्यापारी का व्यापार सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और अपराध करने वालों को सही जगह पहुंचा दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री और बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, एमएलसी सुभाष यदुवंश, गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक

देगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि बहु बेदियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। व्यापारी का व्यापार सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और अपराध करने वालों को सही जगह पहुंचा दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री और बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, एमएलसी सुभाष यदुवंश, गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, विधायक

अजय सिंह, विधायक दुधराम, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, पूर्व विधायक रवि सोनकर, पूर्व विधायक सीपी शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष यशकांत समेत स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री कांपोजिट विद्यालय (पीएमश्री) का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, पर्यटन विकास, छात्रावास निर्माण, नगर पंचायत हरैया में गौशाला व अमृत सरोवर निर्माण और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। लोकार्पण वाली प्रमुख परियोजनाओं में राजकीय पॉलिटेक्निक हरैया, राजकीय महाविद्यालय भवन, अनेक प्रमुख मार्गों का निर्माण व

चौड़ीकरण, सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, पर्यटन विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास के तहत गोटवा-ऊंजी मार्ग, ललहवा-बाबा नग निहाल दास मार्ग, पैकोलिया-शिवाघाट मार्ग के चौड़ीकरण, बाबा भारी नाथ शिव स्थल के पर्यटन विकास, ग्रामीण संपर्क मार्ग और सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख हैं। यहां नगर पंचायत कप्तानगंज के कार्यालय भवन, वेलकम मंडप, विभिन्न ग्रामीण संपर्क मार्ग, सड़क चौड़ीकरण, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और सिंचाई की योजनाओं का लोकार्पण किया।

सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने उत्तरी सीमा पर देखी ऑपरेशनल तैयारी

एलओसी पर तैनात जवानों से मुलाकात में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली



दौरान उन्होंने अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से बातचीत की और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा, स्थिरता और तालमेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। चिनार कॉर्प्स हेडक्वार्टर में उन्होंने ऑपरेशनल तैनाती, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, अंतर-एजेंसी तालमेल, बदलते

सुरक्षा गतिशीलता और चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन्स के पूरे परिदृश्य में प्रौद्योगिकी अवशोषण, क्षमता वृद्धि और एकीकृत युद्ध तैयारी की पहलों का भी रिव्यू किया। जनरल धीरज सेठ ने कुपवाड़ा, उरी

और मानसबल में फॉर्मेशन्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी ग्रिड, निगरानी संरचना, क्षेत्र में नवाचार और परिचालन तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और मुश्किल हालात में शांति और स्थिरता बनाए रखने में

बंद कंपनी से तीन करोड़ रुपये की विदेशी शराब जब्त

मुंबई, 10 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बंद पड़ी कंपनी में पुलिस ने छापा मार कर तीन करोड़ रुपये की विदेशी शराब जब्त की है। इस जब्त की गई विदेशी शराब को गुजरात भेजने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले की गहन छानबीन म्हसवद पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। म्हसवद पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डर रमेश वाघरे ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि उनकी टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक बंद जिनिंग प्रेस में बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी तरीके से विदेशी शराब रखी जा रही है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अश्विनी सनप के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम ने संबंधित जगह पर छापेमारी की।



छापे के दौरान जिनिंग प्रेस के कैम्पस में खड़ी 14 चार पहिया गाड़ियों में भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। साथ ही, आयशर कंपनी का एक ट्रक और टाटा कंपनी का एक कंटेनर शराब की

पेटियों से भरा मिला। पुलिस ने सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया और शराब के स्टॉक की गिनती शुरू कर दी। गुरुवार को दोपहर में शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। शुरूआती अंदाजे के मुताबिक, जब्त विदेशी शराब के स्टॉक, अलग-अलग गाड़ियों और दूसरे सामान की कुल कीमत करीब तीन करोड़ रुपये है। जब्त स्टॉक में कई नामी कंपनियों की विदेशी शराब की बोतलें और बड़ी मात्रा में बीयर शामिल है। कार्रवाई में गैर-कानूनी तरीके से लपटा है कि मुत्तकों में अधिकांश, या संभवतः सभी, विदेशी नागरिक थे। इस हादसे में कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को घुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 150 दमकलकर्मी और पांच दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटे हैं।

तस्करी रैकेट के काम करने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है कि शराब असल में किसकी थी, कहां से लाई गई थी, गुजरात में किसे भेजने की तैयारी थी और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है।

यह ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सनप के नेतृत्व में पुलिस कांस्टेबल मुकेश राठोड़, दादाभाई साबले, विकास कपूरे, अजय पवार, युवराज रावताले, उमेश पवार, राकेश पवार, धीरसिंह वलवी, दीपक पाटिल, प्रवीण पवार और दूसरे पुलिसवालों की टीम ने कामयाबी से पूरा किया है।

गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण पर काहिरा में इजराइल, मिस्र और हमาส की बैठकें जारी

यरूशलेम/काहिरा।

गाजा युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल और मिस्र के सैन्य अधिकारियों के बीच काहिरा में अहम बातचीत हुई। इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक ऐसे समय में हुई जब हमาส का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिस्र की राजधानी में मध्यस्थों के साथ युद्धविराम समझौते के भविष्य पर चर्चा कर रहा है। तुर्किये की सरकारी संवाद समिति अनाडोलू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ इजराइली सैन्य अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दो दिनों से मिस्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता में



शामिल रहा। हालांकि, दोनों देशों ने बैठक में शामिल अधिकारियों की पहचान और बातचीत के नतीजों का खुलासा नहीं किया है। खलील अल-हय्या के नेतृत्व में हमาส प्रतिनिधिमंडल युद्धविराम को तैयार नहीं है। गाजा युद्धविराम को अगले चरण पर मध्यस्थों के साथ

चर्चा के लिए काहिरा पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वाताएं गाजा समझौते के अगले चरण को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। वहीं, इजराइल का दावा है कि हमาส अब भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। गाजा युद्धविराम को लागू कराने और आगे की प्रक्रिया

को आगे बढ़ाने में मिस्र, कतर और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, मिस्र की ओर से इजराइली मीडिया की रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण में गाजा से इजराइली सेना की व्यापक वापसी, पुनर्निर्माण कार्यों की शुरूआत और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर सहमति बनने की परिकल्पना की गई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि किसी भी अगले चरण से पहले फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों का निरस्त्रीकरण प्राथमिक शर्त होना चाहिए, जबकि हमาส इस मांग का विरोध करता रहा है।

लेकिन करूर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

उधर, मुत्तकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने से संबंधित मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दायर याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने भी संबंधित पक्षों को अस्थायी सरकारी नियुक्ति देने का निर्देश दिया।